राष्ट्रीय छात्रशक्ति

शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका

वर्ष : 31 अंक : 2 मार्च–अप्रैल 2008

Shimla (Himachal Pradesh)

Shri Sunil Ambekar, National Organising Secretary, ABVP addressing Tibetan protesters in Jandar Mantar, Delhi

Blood donation camp organised by ABVP Punjab University, Chandigarh Unit.

राष्ट्रीय
छात्रशक्ति
शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका
वर्ष : 31 अंक : 2 ● मार्च–अप्रैल 2008

संरक्षक
अतुल कोठारी
संपादक
डा. मुकेश अग्रवाल
प्रबंध संपादक
नितिन शर्मा

संपादक मंडल
संजीव कुमार सिन्हा
आशीष कुमार 'अंशु'
उमाशंकर मिश्र

डा. रंजीत ठाकुर द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बी–50, क्रिश्चियन कॉलोनी, पटेल चेस्ट, दिल्ली–110007 के लिए प्रकाशित एवं पुष्पक प्रेस, 119, डीएसआईडीसी कॉम्प्लेक्स, ओखला, फेज–1, नई दिल्ली–20 द्वारा मुद्रित

फोन : 011 – 23093238 , 27662477
E-mail : chhatrashakti@gmail.com
Website : www.abvp.org

मूल्य : एक प्रति रुपए 10/–

Veiled Threat!

विषय सूची

प्रमुख लेख

Rise of 'missile woman' 6
तिब्बत की मुक्ति–भारत की सुरक्षा 7
दूरगामी थे 1857 महासमर के परिणाम 9
भूख से नहीं, भीख से मुक्ति आवश्यक 11
सीपीएम और नक्सलवाडी पार्टी में अंतर 13
कम्युनिस्टों के ऐतिहासिक अपराधों की लम्बी दास्तां 15
तीन वर्षों में 16 हजार छात्रों ने की आत्महत्या 17
लाल बादशाह का 'कुजन' पर कोप 23
राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रारित प्रस्ताव 18

परिचर्चा

चीन, तिब्बत – भारत अंतर्संबंध 25
परिषद् गतिविधियां 29

आह्वान

* क्या आप देश की वर्तमान दशा पर चिन्तित हैं?
* क्या आपको दृढ़ विश्वास है कि सामाजिक परिवर्तन लाने में छात्र–युवा ही सक्षम हैं?

यदि हां

* तो अपने क्षोभ को शब्द दीजिए और विश्वास कीजिए,आपमें क्षमता है कलम की नोंक से दुनिया का रुख बदलने की।
* अपने विचारों को साहित्य की किसी भी विधा में शब्द दें तथा राष्ट्रीय छात्रशक्ति द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, 136, नॉर्थ एवेन्यू नई दिल्ली–110001 को प्रेषित करें।

वैधानिक सूचना : राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण सम्बन्धित लेखकों के हैं। सम्पादक, प्रकाशक, एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली रहेगा।

उच्च शिक्षण संस्थानों में ओ.बी.सी. आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत –अभाविप

उच्च शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछडी जातियों (ओ.बी.सी.) के 27 प्रतिशत आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये निर्णय का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्वागत करती है।

अभाविप का स्पष्ट मत है कि अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछडी जातियों को आरक्षण एक ऐतिहासिक अनिवार्यता है। इसे संविधान की परिधि व सामाजिक वास्तविकता की सीमा मे लागू करना आवश्यक है। अभाविप का मानना है कि आरक्षण का लाभ वास्तविक जरूरतमंदो को मिले इसलिये इसमे क्रीमीलेयर लागू करना चाहिए साथ ही साथ इसका लाभ कितने लोगो को मिला है इसकी भी समय–समय पर समीक्षा की जानी चाहिए, जो लोग आरक्षण का लाभ प्राप्त कर आगे बढ चुके है उन्हे आरक्षण की परिधि से बाहर किया जाना चाहिए।

अभाविप मानती है कि आरक्षण जैसे मसलो पर केवल राजनेता या सरकारें निर्णय न करें अपितु समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्तियो जैसे शिक्षाविद् पूर्व न्यायाधीश, समाजसेवक, समाजशास्त्री, छात्रसंगठनो के स[illegible] आदि के सहभाग से ऐसे विषयों पर व्यापक राष्ट्रीय बहस द्वारा ही निर्णय करें।

Unprecedented hike in IIM and IIT fees is injustice: ABVP

The recent decision to steeply hike fees in IIM and the following of suit by IIT is shocking as it is an oppressive step against the student community. A mindset of commercialization of education is being promoted in these institutions of international repute. ABVP protests this decision in strongest possible terms.

ABVP is of the opinion that an independent committee needs to be setup which would decide after a survey as to whether there is a need for a fee hike at all. Students of the institutes are being forced into taking debt to fund their studies. The cycle initiated by them seems to be to first force them to get into debt and then fo[illegible] them into the corporate sector to repay them. While ABVP isn't opposed to periodic fee hikes, it is against arbitrary and unnecessary fee hikes.

Akhil Bharathiya Vidyarthi Parishad calls the student community to treat this arbitrary fee with the concern it deserves. It calls upon them to not take to debt but come out in the open to fight for its rights. Parishad also warns the government that autonomy does not mean commercialization of education.

ABVP also demands that the central government initiate action to reverse the fee hike. In case such action isn't initiated, Parishad will launch a nationwide campaign against the anti-student and unjust decisions of the government. The government may please be ready to face the wrath of the student community if it fails to initiate action.

मंहगाई की मार

संपादकीय

संप्रग शासन में महंगाई बेलगाम है। महंगाई दर थमने का नाम ले नही रही है। 3 मई को खत्म हफ्ते में महंगाई की दर 7.83 फीसदी पर पहुंच गई। देश में चारों ओर हाहाकार है। दो वक्त का भोजन जुटाने में लोगों के पसीने छूट रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में 'कांग्रेस का हाथ–आम आदमी के साथ' का वादा कर कांग्रेस ने जनादेश मांगा था। लेकिन आज आम आदमी का जीना मुहाल है। बढती महंगाई के चलते शिक्षा आम आदमी के पहुंच के बाहर हो रही है, दवाई महंगी हो रही है।

संप्रग सरकार महंगाई को नियत्रित करने के बजाय कोरी बयानबाजी कर रही है और अपनी नाकारापन का ठीकड़ा किसी और के सिर पर फोडना चाहती है। केन्द्रीय मंत्री कपिल सिब्बल का कहना है कि हमारे पास कोई जादू की छडी नही है कि हम इस स्थिति को ठीक कर दें। कृषि मंत्री शरद पवार कहते हैं कि साऊथ के लोगों ने गेहूं खाना शुरू कर दिया है, चावल खाना बंद कर दिया है, इस कारण गेहूं के दाम ज्यादा हो गए हैं। वित्त मंत्री कहते है, बढ़ती महंगाई के लिए राज्य सरकार और अंर्तराश्ट्रीय बाजार जिम्मेदार है। बेलगाम महंगाई कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है बल्कि यह संप्रग सरकार निर्मित आपदा है। यह सरकार के कुप्रबंधन का नतीजा है। केन्द्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा बाजार के हवाले कर दी है। महंगाई कांग्रेस की पहचान बन चुकी है। जब–जब कांग्रेस सत्ता में आती है, महंगाई साथ लाती है। संप्रग की चेयरपर्सन सोनिया गांधी प्रधानमंत्री को सिर्फ पत्र लिखने का नौटंकी करती है। वहीं, सत्ता की चाशनी में डूबे वामपंथी भी बेनकाब हो चुके है। भले ही सरकार लोगों के मुंह का निवाला छीन रही हो वे सिर्फ भौंककर ही संतुश्ट हो लेते है या फिर प्रधानमंत्री के साथ नाश्ता पर गप–शप कर। वे जनता नहीं, सत्ता के साथ रहना चाहते है। जिस सरकार के शासन में लोग दो वक्त का भोजन न जुटा पाए उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। ■

माकपा की कत्ल संस्कृति

केरल का कन्नूर मार्क्सवादी हिंसा से दहल उठा है। यह हिंसा राज्य–समर्थित कत्लेआम है। राज्य में सन् 1958 से कम्युनिस्ट पार्टी का खूनी खेल जारी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) हिंसा के जरिए ही केरल में शासन करती है। जो भी इस आतंक का विरोध करता है, माकपा की स्वपोशित गुंडावाहिनी वहशियाना तरीके से उसकी हत्या कर देते है। ध्यातव्य है कि केरल में जब–जब माकपा सत्तासीन हुई है, तब–तब हिंसा का नंगा नाच हुआ है। राज्य में मई 2006 में माकपा और एलडीएफ की सरकार बनने के बाद मार्क्सवादियों का वीभत्स रूप कन्नूर में सामने आया है। गौरतलब है कि कन्नूर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की साख तेजी से बढ रही है। बड़ी संख्या में लोग राश्ट्रवादी विचारधारा के साथ जुड रहे है। इससे बौखलाकर मार्क्सवादी गुण्डों ने गत 5 मार्च से 7 मार्च के बीच लगातार तीन दिनों तक खूनी खेल खेला और रा. स्व. संघ और भाजपा के पांच युवा कार्यकर्ताओं निखिल, संतोष, महेश, सुरेश बाबू और सुरेन्द्रन पर हमला ही नही किया बल्कि उनके शवों के टुकडे–टुकडे कर दिए। यही नहीं महेश का तो सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया गया था।

इतिहास गवाह है कि मार्क्सवादी हर मोर्चे पर राष्ट्रविरोधी गतिविधियों मे लिप्त रहे हैं। भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जडों को कमजोर करना ही उनका एकमात्र मकसद है। राष्ट्रवादी विचारधारा से उन्हें कडी चुनौती मिल रही है। वैचारिक रूप से मार्क्सवादियों की हार हो चुकी है। उन्हें भारतीय जन–विश्वास प्राप्त नहीं हो रहा है। खास बात यह है कि भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने सन् 1925 में अपना कार्य प्रारंभ किया। रा. स्व. संघ से जुडे संगठन आज देशभर में अपना परचम फहरा रहे है। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में ही सिमट कर रह गई है। इसलिए अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए वे हिंसा की राजनीति का सहारा ले रहे हैं। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन मार्क्सवादियों को लोकतंत्र और देश की कानून–व्यवस्था मे आस्था नहीं है। सर्वविदित है कि तानाशाही कुछ ही समय तक लोगों को दबा पाता है। हिंसा के बल पर कोई भी राजनीतिक दल अधिक समय तक शासन नहीं कर सकते। ■

People

Rise of 'missile woman'

She has come to be known as "Agni Putri"; some call her the "missile woman". Her real name is Tessy Thomas and she had the privilege of working with "missile man" APJ Abdul Kalam before he became the President of India.

Tessy is now set to head the country's key missile project. Her name has been cleared for appointment to the prestigious post of Project Director of the upgraded version of the 2000 km nuclear capable Agni-II missile.

One of the 200 women scientists and technicians working with the DRDO, she has been associated with the Agni projects for the past 20 years. At present she is the Associate Project Director of the 3,000-km range Agni-III missile project.

Tessy, who did the post analysis of the failure of the first Agni-III missile, reportedly said there were some shortcomings in the test of the missile which were overcome for a smooth flawless test flight.

While details of the project have been kept a closely guarded secret, she may work on developing the 700-km Agni ballistic missile system.

With Tessy all set to head the country's key missile project, women have broken into most of the citadels so far considered to be sole male domains. They have risen to the rank of Lt. General and Air Marshal in the armed forces.

She hates if someone calls her gender into question at the work place. "Here, I am a scientist and not a woman", she asserts.

It has been a long journey for Tessy, spanning two decades to get to the top slot. "I have been associated with the Agni Project for the last 20 years and have been Associate Project Director for Agni I, II and III. Now the time has come to head a project for an Agni missile with advanced technology", said the 45-year-old, Hyderabad-based guided missile scientist.

While there are more than 95 women scientists in the DRDO at present, Thomas is the first to become the Project Director of a crucial missile system.

Nearly 20 women scientists are currently involved in the Agni Project itself. Her fascination for the missiles started while she was in school at her home state, Kerala.

During her school days she used to hear about the rocket station at Thiruvanthapuram and would also be fascinated by the Apollo moon mission. "I guess that in my inner mind I always wanted to be involved with rockets and missile", she has reportedly said.Tessy, later, joined the Pune-based Defence Institute of Advanced Technologies to get a master's degree in guided missile system.

She was initiated into the Agni project by India's original "missile man", former President APJ Abdul Kalam, after she joined the DRDO in 1988 as one of the five women scientists in the research organisation.The postgraduation gave her some insight in guidance technology and the moment she joined Dr. Kalam's team, he put her in the guided missile system of the Agni programme.

Her advice to young women is to take science at the school level to go on to become researchers and scientists.

(Excerpts: Tribune)

■

तिब्बत की मुक्ति–भारत की सुरक्षा

– संजीव कुमार सिन्हा –

पराधीनता से हीन कुछ भी नहीं। स्वाधीनता सबको प्रिय है। तिब्बत आज पराधीन है। वह चीनी शिकंजे में फंसा हुआ है। 'समतामूलक समाज' का मुखौटा लगाने वाली विचारधारा 'साम्यवाद' ने तिब्बत के लोगों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया है। आजादी की मांग कर रहे तिब्बतियों पर चीन तरह–तरह से जुल्म ढाने में जुटा हुआ है।

हाल ही में तिब्बतियों पर चीन के दमन–चक्र से पूरी दुनिया जरूर कांप उठी लेकिन किसी को हैरानी नहीं हुई। जिन्हें जरा सा भी कम्युनिस्ट शासन के बारे में पता है वे भलीभांति जानते है कि आतंक के बूते ही कम्युनिस्टों का शासन चलता है। इतिहास गवाह है कि दुनिया भर में वामपंथी दल जहां भी सत्तासीन हुए, वहां उन्होंने अपने विरोधियों को निर्ममता से कुचल डाला। साम्यवाद तानाशाही व साम्राज्यवादी विचारधारा है। इसलिए चीन अपने साम्राज्यवादी मंसूबे को अंजाम दे रहा है।

तिब्बतियों पर चीन के दमन–चक्र से पूरी दुनिया जरूर कांप उठी लेकिन किसी को हैरानी नहीं हुई। जिन्हें जरा सा भी कम्युनिस्ट शासन के बारे में पता है वे भलीभांति जानते है कि आतंक के बूते ही कम्युनिस्टों का शासन चलता है। इतिहास गवाह है कि दुनिया भर में वामपंथी दल जहां भी सत्तासीन हुए, वहां उन्होंने अपने विरोधियों को निर्ममता से कुचल डाला। साम्यवाद तानाशाही व साम्राज्यवादी विचारधारा है। इसलिए चीन अपने साम्राज्यवादी मंसूबे को अंजाम दे रहा है।

इतिहास पर नजर डालें तो यह स्पष्ट है कि तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र रहा है जिसकी अपनी संस्कृति है। तिब्बती शांति के उपासक हैं और बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। सन् 1949 में चीन के कम्युनिस्ट शासकों ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। 1959 में तिब्बती संघर्ष के विफल हो जाने के बाद दलाई लामा ने तिब्बत छोड़कर भारत में राजनीतिक शरण लिया। दलाई लामा तबसे भारत में निर्वासित जिंदगी बिता रहे है। तिब्बती अपने ही देश में गुलामों की तरह जीवन व्यतीत कर रहे है। यहां बड़े पैमाने पर मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। दुनिया भर में तिब्बती स्वाधीनता की अलख जगाए हुए है। चीनी शिकंजे से मुक्ति के लिए तिब्बत का संघर्ष जारी है।

साम्यवादी चीन का इतिहास रक्तरंजित है। चीन में 1960–70 के दशक में सांस्कृतिक क्रांति के नाम पर लोगों पर जुल्म ढाए गए। तिब्बतियों पर जुल्म ढाते हुए तमाम तरह की पाबंदियां लगाई गई। उनकी गतिविधियां केवल पूजा अर्चना तक ही सीमित कर दी गई। 1989 में तिब्बत में व्यापक आंदोलन में हुआ था। इसके कुछ दिन बाद ही बीजिंग में थ्येन आनमन चौराहे पर लोकतंत्र की मांग को लेकर हजारों नौजवान इकट्ठे हुए। साम्यवादी चीन ने प्रदर्शनकारी नौजवानों को निर्ममता से कुचल डाला।

गत 14 मार्च को तिब्बती आंदोलन की 49वीं बरसी पर ल्हासा में तिब्बतियों ने विरोध प्रदर्शन किया। चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाई। लगभग 130 तिब्बती मारे गए। एक हजार से अधिक लोग घायल हुए। इसके अलावा 400 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं चीन सरकार ने मरने वालों की आधिकारिक संख्या 19 बताई है।

तिब्बत में चीनी दमन–चक्र को लेकर भारतीय वामपंथियों का रुख चिंताजनक है। वामपंथी चीन को अपना नियंता मानते हैं और जब भी अवसर आता है राष्ट्रहित को दरकिनार कर वे चीन के पक्ष में मिमियाने लगते है। भाकपा महासचिव ए.बी. वर्धन ने हैदराबाद में कहा कि हम तिब्बत को चीन का अभिन्न अंग मानते हैं। माकपा नेता सीताराम येचुरी ने तिब्बत के मसले को चीन का अंदरूनी मसला बताते हुए कुछ भी कहने से इंकार कर दिया। कोयंबटूर में माकपा कांग्रेस के समय माकपा महासचिव

प्रकाश करात ने कहा कि केंद्र सरकार मानती है कि तिब्बत पूरी तरह से चीन का अभिन्न अंग है और उसे अपने रुख पर कायम रहना चाहिए।

चीन का कहना है कि तिब्बत हमेशा से चीन का अभिन्न अंग रहा है। उसने ल्हासा की घटनाओं के लिए दलाई लामा को जिम्मेदार ठहराया है। यह आरोप निराधार है क्योंकि दलाई लामा ने हिंसा का स्पष्ट विरोध किया है। दरअसल, चीन में ओलंपिक खेलों का आयोजन होना है। तिब्बतियों को आजादी की आवाज बुलंद करने का यह सही समय लगता है। चीन ओलंपिक मशाल को तिब्बत के रास्ते एवरेस्ट पर्वत पर ले जाना चाहता है। उसे यह डर सता रहा है कि यदि तिब्बती आंदोलन करने में सफल हुए तो कहीं ओलंपिक खेल न स्थगित हो जाए।

तिब्बतियों के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ल्हासा की स्थिति को लकर गंभीर रूप से चिंतित है। उन्होंने एक प्रेस वक्तव्य जारी करके चीन से मांग की है कि वह ल्हासा में बर्बर तरीके से बल प्रयोग करना बंद करे। उन्होंने कहा है कि तिब्बतियों ने जो प्रदर्शन किए हैं वह चीनी शासन के खिलाफ लंबे समय से चले आ रहे असंतोष का प्रतीक है। तिब्बतियों के सामने आज अपनी संस्कृति को बचाने का सवाल है।

वामपंथी दलों की बैसाखी पर टिकी संप्रग सरकार चीन को नाराज नहीं कर सकती। इसलिए भारत सरकार माकपा की चाटुकारिता कर रही है। उसने चीन की निंदा नहीं की है, हिंसा पर चिंता प्रकट की है और मामले को बातचीत के जरिए हल करने की सलाह दी है। दूसरी ओर, चीन ने तिब्बत की राजधानी ल्हासा में हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा कराने के लिए 15 देशों के राजनयिकों को चुना है। इनमें भारत नहीं है। प्रमुख देश हैं—अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जापान, तंजानिया, ब्राजील, सिंगापुर, स्पेन, कनाडा और इटली। वहीं, चीनी विदेश मंत्रालय द्वारा भारतीय राजदूत निरुपमा राव को रात 2 बजे भारत में तिब्बती प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त करने के लिए बुलाना चिंता का विषय है।

तिब्बत में चीनी दमन के विरोध में लोगों में गुस्सा व्याप्त है। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान बाइचुंग भूटिया ने ओलंपिक मशाल रिले का बहिष्कार किया। उनका कहना है कि वह हिंसा से नफरत करते हैं और तिब्बत की जनता के साथ एकजुटता दिखाने का यही एक रास्ता है। विश्व भर में तिब्बत में चीनी दमन के मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया हुई है। अमेरिका ने तिब्बतियों पर चीनी दमन का स्पष्ट विरोध किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज बुश ने चीनी राष्ट्रपति हू जिंताओ को फोन पर तिब्बत में प्रदर्शनकारियों के दमन पर चिंता व्यक्त की। फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी ने तिब्बत में रक्तपात पर स्पष्ट रूप से चीन को ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार की धमकी दी है। यूरोपीय यूनियन के विदेशमंत्री विचार कर चुके हैं कि 8 अगस्त को ओलंपिक के उद्घाटन का बॉयकॉट किया जाए। चेक गणराज्य, पोलैंड और एस्तोनिया ने भी समारोह से दूर रहने की बात कही है। हद तो तब हो गई जब भारत में ओलंपिक मशाल रिले के दौरान केन्द्र सरकार ने चीन के सामने समर्पण कर दिया। चीनी सुरक्षा अधिकारियों की देख-रेख में रिले संपन्न हुआ। पूरे दिन दिल्लीवासी परेशान रहे। मेट्रो रेल बंद रहे। सांसद तक को परेशान किया गया। आम लोगों के साथ क्या हुआ इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।

स्वामी विवेकानंद ने चीन को दैत्य बताया था। इतिहास साक्षी है कि तिब्बत पर कब्जा जमाने से पहले चीन हमारा कभी पड़ोसी देश नहीं रहा। एक ओर जहां हमारा देश अशिक्षा, भूख, कुपोषण से बेहाल है वहीं हमें नाहक अरबों रुपए भारत-चीन सीमा रक्षा पर खर्च करना पड़ रहा है। आज यह जरूरी हो गया है कि भारत चीन से दबे नहीं। तिब्बत के साथ खड़े हों, इसी में हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा सन्निहित है। तिब्बत समस्या के मुद्दे पर भारत को व्यापक परिप्रेक्ष्य में सोचते हुए ठोस पहल करनी चाहिए और राजनीतिक दबावों से ऊपर उठकर राष्ट्रहित को प्रमुखता देनी चाहिए। ■

दूरगामी थे 1857 महासमर के परिणाम

1857 का स्वातंत्र्य समर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के अन्यायपूर्ण शोषण और भारतीय समाज तथा स्वधर्म पर उसके अंग्रेज अधिकारियों द्वारा योजनाबद्ध रूप से किये जा रहे सांस्कृतिक आक्रमण के प्रतिकार के लिये किया गया राष्ट्रव्यापी प्रयास था जिसमें देश के हर प्रान्त तथा समाज के हर वर्ग ने भाग लिया था।

1857 के महासमर से पूर्व एक सहस्राब्दी का इतिहास विदेशी आक्रान्ताओं के आक्रमण और उनके प्रतिकार का क्रमागत विवरण ही रहा है। परिणामस्वरूप युद्धकाल में प्रदर्शित शौर्य ही भारतीय सामाजिक व राजनैतिक नेतृत्व की पहली योग्यता बनी। शांतिकाल की सहज-सामान्य प्राथमिकताओं से इतर समाज और राजनीति का केन्द्र बिन्दु राजाओं और सेनाओं के इर्द-गिर्द बना रहा। यह कहा जा सकता है कि 1857 का स्वातंत्र्य समर इस एक हजार साल पुरानी राजनैतिक प्रणाली का अंतिम सामूहिक प्रयास था। साथ ही, इस विद्रोह की समाप्ति ने ब्रिटिश सैनिक अभियान को पूर्णता के शिखर पर पहुंचा दिया।

1857 का स्वातंत्र्य समर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के अन्यायपूर्ण शोषण और भारतीय समाज तथा स्वधर्म पर उसके अंग्रेज अधिकारियों द्वारा योजनाबद्ध रूप से किये जा रहे सांस्कृतिक आक्रमण के प्रतिकार के लिये किया गया राष्ट्रव्यापी प्रयास था जिसमें देश के हर प्रान्त तथा समाज के हर वर्ग ने भाग लिया था।

विद्रोह के दमन के बहाने अंग्रेजों ने पूरे भारत पर अपना एकछत्र राज्य स्थापित कर लिया। देश भर में उन्होंने भय और आतंक का वातावरण पैदा किया ताकि भविष्य में कोई उनसे टकराने का साहस न कर सके। इसके विपरीत भारतीय समाज ने इस घटनाक्रम से यह निष्कर्ष निकालने में कोई चूक नहीं की कि अंग्रेजों की अजेयता को चुनौती दी जा सकती है, उन्हें पराजित किया जा सकता है।

सभी पक्षों ने क्रांति के परिणामों का अपनी-अपनी दृष्टि से आकलन किया और भविष्य के लिये अपने मार्ग निश्चित किये। अंग्रेजों के अतिरिक्त क्रांति के समय हम हिन्दू, मुस्लिम, वहाबी मुस्लिम व सिख मतावलम्बियों, सामंतों, सन्यासियों, पत्रकारों, देशी सैनिकों आदि अनेक वर्ग व समुदायों को एक साथ संघर्ष करते देखते हैं, वहीं क्रांति के पश्चात् इन सभी को बंटा हुआ और राजनैतिक हिताहित के अनुसार विशिष्ट स्थिति में खड़ा हुआ पाते हैं।

क्रांति से पहले सेना के अंदर और नागरिकों के बीच धर्मान्तरण के जो सघन प्रयास अंग्रेजों ने प्रारंभ किये थे, बाद में उनकी गति काफी धीमी कर दी गयी। समाज के विभिन्न वर्गों के बीच खाई पैदा कर बांटो और राज करो की नीति अपनायी गयी। न केवल हिन्दुओं और मुस्लिमों को, अपितु हिन्दू समाज के विभिन्न घटकों को भी समान्तर और एक-दूसरे के विरुद्ध खड़ा करने के प्रयास किये गये।

स्वातंत्र्य समर से ठीक पहले 1865 में हुई जनगणना में पंजाब में सिखों की गणना हिन्दू शीर्षक के अंतर्गत की गयी लेकिन 1865 में हुई अगली जनगणना में सिखों को हिन्दुओं से अलग वर्गीकृत किया गया। अंग्रेजी पढ़े-लिखे दिमागों में यह बैठाया गया कि जाति विभेद ही भारत के पतन का मूल कारण है, जबकि अपनी ओर से उन्होंने जाति

व्यवस्था को दृढ़ करने का ही प्रयत्न किया। यहां तक कि अपनी सेना में भर्ती भी जातियों के आधार पर करनी शुरू की और सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट आदि नाम दिये।

यदि इस संघर्ष को ईस्ट इंडिया कंपनी की कारगुजारियों के खिलाफ उठे एक तीव्र आक्रोश तक सीमित करते हैं तो इसे संघर्ष की सफलता ही माना जायेगा कि अगस्त 1858 में भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत का नियंत्रण प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटेन ने अपने हाथ में ले लिया।

यदि इस संग्राम को व्यापक फलक पर लें तथा इसे भारतीयों के स्वधर्म पर अंग्रेजों द्वारा किये जा रहे सांस्कृतिक आक्रमण के विरुद्ध भारतीय प्रतिरोध का प्रयास मानें तो भी यह इस आंदोलन की जीत ही थी कि रानी विक्टोरिया को अपनी घोषणा में स्पष्ट कहना पड़ा कि भारत में सबको अपने धर्म पर आचरण करने का अधिकार दिया जायेगा।

1857 के स्वातंत्र्य समर जैसी घटनाएं किसी देश के इतिहास में कभी–कभी ही घटती हैं। भारत के इतिहास में भी यह अभूतपूर्व थी। ब्रिटिश इतिहासकारों के अनुसार इस क्रांति में कम से कम चार करोड़ भारतीय सम्मिलित हुए। क्रांति के विस्तार का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि जितने बड़े भाग में क्रांति हुई उसमें यूरोप के फ्रांस, ऑस्ट्रिया और पर्शिया जैसे तीन देश समा सकते थे।

दुनिया के तमाम देशों की संप्रभुता को निगल कर उन्हें अपना उपनिवेश बना चुके अंग्रेजो को 1857 के स्वातंष्य समर ने यह स्वीकार करने पर बाध्य कर दिया कि वे इस देश को पाशविक शक्ति के प्रयोग अथवा धर्मान्तरण के द्वारा अपना स्थायी उपनिवेश नहीं बना सकेंगे। 'फूट डालो–राज करो' की जो नीति अंग्रेजों ने 1857 के बाद अपनायी वह इस स्वीकारोक्ति का ही प्रमाण है कि यदि भारत में जिस प्रकार की सामाजिक एकता स्वातंष्य समर के दौरान देखने को मिली, वह बनी रहती है तो कितने भी बलप्रयोग के बावजूद भारत को लम्बे समय तक अपने नियंत्रण में रख पाना संभव नहीं होगा।

फॉरिस्ट ने अपने ग्रंथ की भूमिका में लिखा–'सन 1857 की इस क्रांति ने हमें यह स्मरण करा दिया है कि हमारा आधिपत्य एक पतली परत पर आधारित है और समाज सुधार तथा धार्मिक क्रांति के विस्फोटों से यह परत किसी भी समय नष्ट हो सकती है। भारतीय क्रांति से इतिहासकारों को अनेक शिक्षाएं मिल सकती हैं, किन्तु उसमें इससे बढ़ कर कोई अन्य महत्वपूर्ण शिक्षा नहीं है कि भारत में ब्राह्मण और शूद्र, हिन्दू और मुसलमान हमारे (अंग्रेजों के) विरुद्ध संगठित होकर क्रांति कर सकते हैं।

जहां तक स्वराज्य प्राप्ति की बात है, देश के विभिन्न हिस्सों में हुए सैन्य संघर्षों में टुकड़ों–टुकड़ों में जीत हासिल की गयी किन्तु उसे स्थायी विजय में नहीं बदला जा सका। जीत कर भी हार जाने का यह दुर्भाग्य शायद इस ऐतिहासिक स्वातंष्य समर की कुण्डली में तभी लिख दिया गया था जब क्रांति का समय से पहले विस्फोट हो गया। क्षोभ के कारण विचार करने का समय न मंगल पांडे को दिया और न मेरठ के सैनिकों को ही। परिणाम की परवाह किये बिना उन्होंने हथियार उठा लिये और उनकी इस जल्दबाजी की कीमत तीन लाख से अधिक लोगों को अपना जीवन देकर चुकानी पड़ी, साथ ही दहलीज तक आ पहुंची स्वतंत्रता 90 वर्षों के लिये हाथ से फिसल गयी।

प्रथम दृष्टया इसके अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो सके इसलिये यह धारणा बनी कि यह महान क्रांति असफल हो गयी। तत्कालीन शासक वर्ग के लिये भी यही अनुकूल था इसलिये उसने इसे एक असफल सैन्य विद्रोह की सीमा में ही बांधने की कोशिश की, हालांकि स्वयं उनके दस्तावेज ही अंग्रेजों के इस झूठ की कलई खोलते हैं।

1857 के स्वातंष्य समर जैसी घटनाएं किसी देश के इतिहास में कभी–कभी ही घटती हैं। भारत के इतिहास में भी यह अभूतपूर्व थी। ब्रिटिश इतिहासकारों के अनुसार इस क्रांति में कम से कम चार करोड़ भारतीय सम्मिलित हुए। क्रांति के विस्तार का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि जितने बड़े भाग में क्रांति हुई उसमें यूरोप के फ्रांस, ऑस्ट्रिया और पर्शिया जैसे तीन देश समा सकते थे। कानपुर, झांसी, अवध जैसे प्रमुख केन्द्रों सहित सैकड़ों महत्वपूर्ण स्थान तथा एक लाख वर्ग मील से अधिक भूमि अंग्रेजों को पराजित कर जीत ली गयी। ■

भूख से नहीं, भीख से मुक्ति आवश्यक

– आशुतोष भटनागर –

भारत में चुनावी महाभारत की उलटी गिनती शुरू हो गयी है। कर्नाटक में चुनाव का बिगुल बज चुका है। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इस साल के अंत तक चुनाव हो जाने हैं। ऐसे में अगर खाद्यान्न की कमी और मंहगाई में वृद्धि हो तो उसकी कीमत तो चुनाव में सत्तारूढ़ दल को ही चुकानी पड़ती है।

जाहिर है सत्तारूढ़ गठबंधन की अध्यक्ष को इससे चिन्तित होना चाहिये। वे हुई भी। उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की। लाड़ले 'युवराज' ने भी टिप्पणियां जड़ीं। जनता से हमदर्दी जताई, वाहवाही बटोरी। काम खत्म। आम आदमी के सवाल पर गांधी–नेहरू खानदान की भूमिका अब यहां आकर समाप्त हो जाती है। इसके आगे का काम प्रधानमंत्री और कांग्रेस प्रवक्ता संभालते हैं।

केवल कर्ज और अनुदानों के भरोसे अर्थव्यवस्था को घसीटने का नाम सरकार नहीं है। भीख की प्रवृत्ति से मुक्ति पा सके तो भूख पर अवश्य विजयी होंगे।

चिंतन–मंथन के दौर चले। यूरोप–अमेरिका से पढ़कर लौटे अर्थशास्त्री सर से सर जोड़ कर बैठे तो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि चुनाव के साल में अगर मंहगाई की जिम्मेदारी अपनी सरकार पर न आये तभी अच्छा। पुराना फार्मूला एक बार फिर आजमाने की बात तय हुई. अपनी गलती दूसरे के खाते में डालो। बयान आ गया– सारी दुनियां में मंहगाई बढ़ रही है इसलिये अपने यहां भी बढ़ रही है।

सरकार को कंधा दे रहे वामपंथियों ने हाय–तौबा मचानी शुरू की। स्यापा अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि बात अमेरिका तक जा पहुंची। दुनियां के बाजार पर आरोप लगे तो ठेकेदार बुश को जवाब देना जरूरी। इधर मनमोहन सिंह, चिदंबरम, अहलूवालिया तो उधर ब्राजील के राष्ट्रपति, अमेरिका के विदेश मंत्री और खुद जॉर्ज बुश। अर्थशास्त्र के एक ही सिद्धांत के व्याख्याकार। एक ही थैली के चट्टे–बट्टे।

अमेरिका में भी चुनाव का साल। खामोश रहें तो कैसे। कॉंडेलिजा राइस को बीच में कूदना पड़ा। बोली– भारत और चीन के लोगों की भूख बढ़ रही है। अगर इन दोनों देशों के लोग कम भोजन करने लगें तो अन्य जरूरतमंद देशों के लिये खाद्यान्न की उपलब्धता बढ़ जायेगी। गजब का आइडिया।

वित्तमंत्री चिदंबरम ने जनता से धीरज रखने को कहा। विदेश राज्यमंत्री आनंद शर्मा बोले सरकार लोगों को जरूरत के हिसाब से बखूबी खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है। आडवाणी ने आलोचना की । जेटली ने जवाबी आंकड़े प्रस्तुत किये। प्रवक्ताओं की नयी फौज भी मैदान में उतरी। भाजपा के प्रकाश जावडेकर बोले तो कांग्रेस के मनीष तिवारी कैसे चुप रहें। वह भी बोले।

इटली के प्रधानमंत्री रोमानो प्रोदी ने जैवईंधन की फसलों के कारण खाद्यान्न संकट की बात छेड़ दी। लगा कि कॉंडेलिजा राइस की बात पूरा दबाव नहीं बना पा रही है। आखिरकार 'आका' बुश को खुद रिंग में उतरना पड़ा। कहा कि भारत के मध्यम वर्ग के लोग समृद्ध हो रहे हैं इसलिये अच्छा व पौष्टिक भोजन मांग रहे हैं। इसी वजह से कीमतें और खाद्यान्न संकट बढ़ रहा है। दूर की कौड़ी लाये बुश। समस्या वापस भारत के पाले में और समृद्धि के लिये तो वे अपनी पीठ खुद ही ठोक सकते हैं। आखिर समृद्धि से दमकते चेहरों की नयी खेप तो उन्हीं के वैश्वीकरण की ईजाद है।

बात यहीं नहीं रुकी। विश्व बैंक के अध्यक्ष रॉबर्ट जोलिक ने बताया कि दुनियां भर में खाद्यान्न की कीमतों में आये अचानक उछाल से 33 देशों में अस्थिरता उत्पन्न हो गयी है। मिश्र, पाकिस्तान और इण्डोनेशिया सहित अनेक देशों में हालात यहां तक पहुंच गये हैं कि बड़ी मात्रा में खाद्यान्न की ढुलाई के समय खाद्यान्न के साथ सेना तैनात करनी पड़ रही है ताकि जनता उसे लूट न ले। उत्तरी अफ्रीका के मौरीतानिया, मोजांबिक, सेनेगल, आइवरी कोस्ट और कैमरून में अन्न के कारण हुई हिंसा में सौ से अधिक जानें जा चुकी है।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अपने आंकड़े पसारे। उसके अनुसार खाद्यान्नों के दामों में 30 प्रतिशत वृद्धि केवल इसलिये

हुई है क्यों कि अमेरिका और यूरोपीय देश खाद्यान्नों का उपयोग अपनी गाड़ियों के लिये जैव ईंधन बनाने में कर रहे है।

मांसाहार को भी इसका परोक्ष कारण बताया गया। मांस की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये अधिक पशु पाले जा रहे है। अभी तक खाद्यान्न उत्पादन करने वाली लाखों हेक्टेयर भूमि पर अब इन पशुओं के लिये चारा उगाया जा रहा है। विशेषज्ञो ने बताया कि एक व्यक्ति की जरूरत का अन्न उत्पादन करने के लिये जितनी कृषि भूमि जरूरी है उससे पांच गुना अधिक भूमि की आवश्यकता तब होती है जब उसी व्यक्ति के मांसाहार के लिये काम आने वाले पशुओं के लिये चारा उगाया जाय।

बात शुरू हुई थी दो गृहस्थी चलाने वाली महिलाओं के बीच, बढ़ते आटे–दाल, सब्जी के भाव को लेकर। बढ़ते–बढ़ते जा पहुंची संयुक्त राष्ट्र संघ तक। चर्चा बहुत हुई। सब जबानी जमा–खर्च। समस्या का हल कहीं नहीं दिखता। दिखे भी कैसे? हम खुद अपने गरेबान में न झांकें तो निदान कैसे हो। हमारे यहां भी मक्का–बाजरा छोड़कर एथनॉल के लिये जट्रोफा उगाया जा रहा है। हमारे देश में भी कल तक जिन खेतों में गेंहू और धान की सुनहरी बालियां झूमती थीं वहां आज गेंदा, गुलाब और ग्लायडोलस लहरा रहे है। हमारे यहां भी नंदी ग्राम में किसान की छाती गोलियों से छलनी कर विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापित किये जा रहे है।

भारत की समस्याओं के समाधान के लिये भारतीय दृष्टि चाहिये। दुनिया को अमेरिकी अहंकार के तले कुचलते बुश के आज्ञापालक किराये के अर्थशास्त्रियो के भरोसे 'राज्य' जी सकते है, स्वाभिमानी 'राष्ट्र' नहीं। समाधान एक ही है, भारत को जागना होगा। अपनी समस्याओं के हल खुद ढूंढने होंगे। बुश जैसे दानवी शक्ति और ओछी सोच के लोगों की आंखों में आंखें डाल कर कहने का साहस करना होगा कि हमें उनकी कृपा नहीं चाहिये।

संप्रभु देश के स्वाभिमानी नागरिक के नाते हमें भी इस प्रश्न पर विचार करना होगा कि क्या भारत का वर्तमान नेतृत्व इसका साहस रखता है? केवल कर्ज और अनुदानों के भरोसे अर्थव्यवस्था को घसीटने का नाम सरकार नहीं है। भीख की प्रवृत्ति से मुक्ति पा सके तो भूख पर अवश्य विजयी होंगे। ■

Bangladeshi Migrants a Threat to Security: Parliamentary Panel

Illegal Bangladeshi immigrants, present in large numbers across the country, pose a grave threat to India's internal security, a Parliamentary panel has noted. A large presence of illegal Bangladeshi immigrants poses a grave threat to the internal security and it should be viewed strongly, the Parliamentary Standing Committee on Home Affairs said in its latest report. The Committee, headed by Sushma Swaraj, also said in its 46-page report that counterfeit notes were in large circulation along the Indo-Bangladesh border.

The Committee strongly recommends that movement along the border may be strictly monitored, the report on Demands for Grants of the Home Ministry said.

The report pointed out that the porous Indo-Bangla border and the practical difficulties due to topographical reasons acting as impediments in the timely completion of border works projects were reasons behind influx of illegal Bangladeshi migrants. It has been reported that these illegal migrants have been able to secure ration cards, driving licenses, voter identity cards and even PAN cards, the report said. It also quoted media reports, citing intelligence sources, as saying that terrorist groups have been recruiting Bangladeshis in India.

Reports have appeared that certain Bangladeshi insurgent groups have been involved in terrorist incidents in India, the report said.

सीपीएम और नक्सलवाड़ी पार्टी में अंतर - कन्नूर से दिल्ली तक

– डा0 कुलदीप चन्द अग्निहोत्री –

जब देश में सीपीएम से टूटकर नक्सलवाड़ी पार्टी का जन्म हुआ था तो साम्यवादी क्षेत्रों में वैचारिक घमासान मचा था। आस्था में दोनों पार्टियां कार्लमॉर्क्स की पूंछ ही पकडे हुए थी। सत्ता पर कब्जा करना है यह दोनों का ही लक्ष्य था और सत्ता पर कब्जा सर्वहारा वर्ग के कल्याण के लिए करना है – इसको लेकर भी दोनों में कोई मतभेद नही था। मतभेद का प्रश्न था कि सत्ता पर कब्जा करने के लिए किन–किन साधनों का उपयोग किया जाए। इस चौराहे पर साम्यवादियों में मतभेद उत्पन्न हो गए। राजनीति के रास्ते पर लंबा सफर तय करने के बाद कुछ साम्यवादियों को लगने लगा था कि सत्ता की प्राप्ति संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से भी हो सकती है और यही मार्ग श्रेयस्कर है। परन्तु इन्हीं के कुछ भाई बंधु इस विश्लेषण से सहमत नहीं हुए। उनका मानना था कि संसदीय लोकतंत्र पूंजीवादियों का पाखंड है और यह रास्ता अंततः पूंजीवाद की ओर ही ले जाता है। सत्ता तो वर्ग संघर्ष के रास्ते से ही प्राप्त की जानी चाहिए और माओ ने इसमें अपना मंत्र भी जोड दिया था कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। इस प्रकार सीपीएम जब दो फाड़ हुई तो बहुत से समाज विज्ञानियों और समाजसेवियों ने ऐसा विश्वास कर लिया कि नक्सलवाड़ी (जिसके बाद में कई गुट बन गए) पार्टी तो हिंसा का रास्ता अख्तियार कर रही है और सीपीएम ने संसदीय लोकतंत्र का शांतिपूर्ण रास्ता चुन लिया है। तब सीपीएम वालों को अनेक जगह से बधाइयां भी मिली और उन्होंने उन बधाइयों को मंद–मंद मुस्कान से स्वीकार भी कर लिया।

सीपीएम की मानसिकता में ही तानाशाही और हिंसा भरी हुई है। उसका प्रयोग वह स्थान और समय देखकर करती है। पश्चिम बंगाल में वही हिंसा गोली बन जाती है और दिल्ली में वहीं हिंसा पत्थर के रूप में प्रकट होती है। यही स्थिति केरल में कण्णूर की है। सीपीएम को केरल में भी सत्ता पर स्थाई कब्जा जमाना है। फिलहाल वह सत्ता में बनी हुई है। संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से सत्ता प्राप्त करके सीपीएम उसे गोली के बल पर स्थाई बनाना चाहती है।

लेकिन सीपीएम और नक्सलवाड़ी पार्टी के किरदारों को देखकर लगता है कि दोनों एक ही रास्ते के राहगीर हैं। रणनीति के तौर पर उन्होंने अलग–अलग रास्ते अपना रखे हैं। सुविधा के लिए उन्होंने इन दोनों रास्तों को जोड़ने के लिए भीतर से इतनी सुरंगे बनाई हुई हैं कि वहां झांकने पर दोनों का ऊपरी अंतर समाप्त हो जाता है।

पिछले दिनों 9 मार्च को दिल्ली में सीपीएम के कार्यालय के बाहर, सड़क के दूसरी ओर, दिल्ली के कुछ शांतिप्रिय नागरिक विरोध स्वरूप एकत्रित हो रहे थे। उनके विरोध करने का मुद्दा यह था कि केरल में सीपीएम की गुंडागर्दी के चलते अनेक निर्दोष नागरिकों की हत्या की जा चुकी है। पिछले कुछ ही दिनों में कण्णूर जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के छः

स्वयंसेवकों को सीपीएम के लोगों ने अमानुषिक ढंग से मार दिया। पूरे कण्णूर जिले में सीपीएम के केडरों का आतंक फैला हुआ है। कुछ हत्याएं तो केरल के गृह मंत्री बालकृष्णन के क्षेत्र में ही हुई। केरल में सीपीएम का शासन है और वहां शासन तंत्र सीपीएम की गुंडागर्दी को समाप्त करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से उनका साथ ही दे रहा है। सीपीएम के इस व्यवहार से केरल की जनता में हताशा है।

दिल्ली में हिन्दू मंच समेत कुछ संगठनों ने सीपीएम के कार्यालय के बाहर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन इसलिए किया ताकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजधानी में सीपीएम को यह पुनः याद दिलाया जा सके कि उन्होंने स्वयं ही संसदीय लोकतंत्र के शांतिपूर्ण रास्ते पर चलने का निर्णय किया हुआ है इसलिए वे केरल में अन्य विचारधाराओं का सामना तर्क से करें न कि उसका जवाब गोली से दें। शायद ये सत्याग्रही यह संकेत भी देना चाहते हों कि गोली का रास्ता नक्सलवाड़ी पार्टी का रास्ता है। सीपीएम संसदीय लोकतंत्र के रास्ते के प्रति ही प्रतिबद्धित है। सीपीएम की केन्द्रीय समिति की बैठक हो रही थी। इसलिए यह आशा और भी बंधती थी कि सीपीएम का शीर्ष नेतृत्व सत्याग्रहियों की इस वेदना को समझेगा। लेकिन दुर्भाग्य से सीपीएम कार्यालय की छत से भयंकर पथराव होने लगा। जिससे कई सत्याग्रही बुरी तरह से घायल हुए। दुर्भाग्य से पुलिस भी मूक दर्शक बनी रही। उसने कार्यालय के भीतर जाकर उपद्रवियों को पकड़ना उचित नहीं समझा। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि सीपीएम कार्यालय की छत पर इतनी बड़ी संख्या में पत्थर कहां से आए? क्योंकि दिल्ली में भी सीपीएम की सत्ता में भागीदारी है। इसलिए पुलिस ने सीपीएम के कार्यालय के भीतर से हो रही पत्थर बाजी को रोकने की बजाय सत्याग्रहियों पर अश्रु गैस के गोले छोड़ने शुरू कर दिये।

दिल्ली की इस घटना को पश्चिमी बंगाल के नंदीग्राम और केरल के कण्णूर जिला की घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। पश्चिमी बंगाल सीपीएम का अपना किला है। जिस पर उसने पिछले तीस सालों से कब्जा किया हुआ है। इसलिए जब नंदीग्राम में लोगों ने सीपीएम के खिलाफ शांतिपूर्ण सत्याग्रह किया तो वहां सीपीएम के कैडर ने उसका जवाब गोली से दिया। अनेक लोग मारे गए। पश्चिमी बंगाल की पुलिस ने भी नंदीग्राम के लोगों को चुप कराने के लिए गोली का ही प्रयोग किया। पश्चिमी बंगाल क्योंकि सीपीएम का वर्चस्व वाला क्षेत्र है। इसलिए वह वहां बेधड़क होकर गोली चला सकती है। इसलिए वहां उसने किसी और विकल्प का प्रयोग नहीं किया सीधे-सीधे गोली का ही प्रयोग किया। दिल्ली में सीपीएम का वर्चस्व नहीं है। इसलिए यहां वह केवल पत्थर का ही प्रयोग कर सकती है। प्रश्न गोली या पत्थर का नहीं है प्रश्न मानसिकता का है।

सीपीएम की मानसिकता में ही तानाशाही और हिंसा भरी हुई है। उसका प्रयोग वह स्थान और समय देखकर करती है। पश्चिमी बंगाल में वही हिंसा गोली बन जाती है और दिल्ली में वही हिंसा पत्थर के रूप में प्रकट होती है। यही स्थिति केरल में कण्णूर की है। सीपीएम को केरल में भी सत्ता पर स्थाई कब्जा जमाना है। फिलहाल वह सत्ता में बनी हुई है। संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से सत्ता प्राप्त करके सीपीएम उसे गोली के बल पर स्थाई बनाना चाहती है। केरल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विद्यार्थी परिषद् और भाजपा के कार्यकर्ताओं की क्रूर हत्याओं के पीछे सीपीएम की यही मानसिकता काम करती है। इस बीराहे पर सीपीएम और नक्सलवाड़ी पार्टी एक दूसरे के बगलगीर दिखाई देते हैं। दोनों अंदर से जुड़े हुए हैं समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। दोनों में अलिखित समझौता दिखाई देता है कि उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई भी रास्ता अख्तियार किया जा सकता है। के.पी.एस. गिल ने एक बार कहा था कि आतंकवादी दो प्रकार के होते हैं। एक वे जो बंदूक लेकर घूमते हैं और दूसरे वे जो उन बंदूकधारियों के गिरतार हो जाने पर मानवाधिकार के नाम पर उन्हें छुड़ाने के लिए तमाम संसदीय प्रक्रियाओं का दुरुपयोग करते हैं।

सीपीएम और नक्सलवाड़ी पार्टी का भी यह रिश्ता धीरे-धीरे स्पष्ट होता जा रहा है। देश के अनेक जिलों विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर नक्सलवाड़ी पार्टी ने कब्जा कर रखा है और जब इन माओवादियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की बात उठती है तो सीपीएम सबसे आगे होकर यह हल्ला मचाती है कि इनके साथ शांतिपूर्वक बातचीत करनी चाहिए। कण्णूर, नंदीग्राम और दिल्ली की घटनाएं सीपीएम और नक्सलवाड़ी पार्टी के भीतर के रिश्ते को और बाहर की रणनीति को अत्यंत स्पष्ट करती है। जिसे सभी राजनीति दलों को समझना होगा तभी इस घातक गठबंधन को पराजित किया जा सकता है। फिलहाल दिल्ली की घटना ने सीपीएम के संसदीय लोकतंत्र के प्रति पाखंड को तो उजागर कर ही दिया है। ■

कम्युनिस्टों के ऐतिहासिक अपराधों की लम्बी दास्तां

राष्ट्र के हर महत्वपूर्ण मोड़ पर वामपंथी मस्तिष्क की प्रतिक्रिया राष्ट्रीय भावनाओं से अलग ही नहीं उसके एकदम विरूद्ध रही है।

सोवियत संघ और चीन को अपना पितृभूमि और पुण्यभूमि मानने की मानसिकता उन्हें कभी भारत को अपना न बना सकी।

भारत के विभाजन के लिए कम्युनिस्टों ने मुस्लिम लीग का समर्थन किया।

कम्युनिस्टों ने 1942 के भारत–छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजों का साथ देते हुए देशवासियों के साथ विश्वासघात किया। 1962 में चीन के भारत पर आक्रमण के समय चीन की तरफदारी की। वे शीघ्र ही चीनी कम्युनिस्टों के स्वागत के लिए कलकत्ता में लाल सलाम देने को आतुर हो गए। चीन को उन्होंने हमलावर घोषित न किया तथा इसे सीमा विवाद कहकर टालने का प्रयास किया। चीन का चेयरमैन–हमारा चेयरमैन का नारा लगाया।

इतना ही नहीं, श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने शासन को बनाए रखने के लिए 25 जून, 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा कर दी और अपने विरोधियों को कुचलने के पूरे प्रयास किए तथा झूठे आरोप लगातार अनेक देशभक्तों को जेल में डाल दिया। उस समय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी श्रीमती इंदिरा गांधी की पिछलग्गू बन गई। डांगे ने आपातकाल का समर्थन किया तथा सोवियत संघ ने आपातकाल को अवसर तथा समय अनुकूल बताया।

कम्युनिस्टों ने सुभाषचन्द्र बोस को तोजो का कुत्ता, जवाहर लाल नेहरू को साम्राज्यवाद का दौड़ता कुत्ता तथा सरदार पटेल को फासिस्ट कहकर गालियां दी।

कम्युनिस्टों से अपेक्षा की जाती है कि वे सर्वहारा के प्रति संवेदनशील होंगे। परन्तु यह संवेदनशीलता तो उनके बीच जीने और मरने में होती है। सीपीएम वाले बता दें कि अपनी स्थापना के बाद से देशभर में उन्होंने कितनी बार मजदूर–किसानों के संघर्ष का नेतृत्व किया है। इसके कितने कामरेड जेल गए हैं। सच तो यह है कि सीपीएम नेता सामूहिक रूप से एक ही बार जेल गए और वह भारत–चीन युद्ध के समय चीन की तरफदारी करते हुए भारतीय राज्य के खिलाफ विद्रोह करने की तैयारी के आरोप में। आज सीपीएम नेतृत्व सर्वहारा को छोड़कर कारपोरेट व व्यावसायिक घरानों का सिपाही हो गया है। यह विडंबना नहीं, चरित्र है। सर्वहारा विरोधी चरित्र और स्टालिनवादी चाल, माओवादी धूर्तता के साथ सीपीएम अपने नए पूंजीवादी दोस्तों के साथ रंग की नहीं खून की होली खेलने में जनहित देख रही है।

माकपा चाहे सत्ता में हो या न हो, यह सीधे या उल्टे तरीकों से पैसा इकट्ठा करती रहती है। केरल में माकपा ने, कहा जाता है कि 5 हजार करोड़ रुपए की सम्पदा इकट्ठी कर ली है। माकपा कट्टर साम्प्रदायिक मुस्लिम और ईसाई गुटों से अवसरवादी गठजोड़ करके पैसे की दृष्टि से सबसे अमीर पार्टी बन गई है। आज यह ऐसे कारपोरेट समूह की शक्ल में दिखती है जिसकी न जाने कितनी सम्पत्ति यहां–वहां बिखरी है।

कामरेड खुद को भले ही सर्वहारा वर्ग की पार्टी बताते हों मगर पिछले 5 दशकों में पार्टी की केरल इकाई 5 हजार करोड़ रुपए की स्वामी बन गई है।

30 वर्ष से पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी राज में समस्याओं का अम्बार लगा हुआ है। कोलकाता की गलियों में घूमने के बाद साबित करने की जरूरत नहीं है कि मार्क्सवादी विचारधारा भारत की समस्याओं का हल नहीं है।

महात्मा गांधी ने आजादी के पश्चात् अपनी मृत्यु से तीन मास पूर्व 25 अक्टूबर, 1947 को कहा–

"कम्युनिस्ट समझते है कि उनका सबसे बडा कर्त्तव्य सबसे बड़ी सेवा–मनमुटाव पैदा करना, असंतोष को जन्म देना और हड़ताल कराना है। वे यह नही देखते कि यह असंतोष, ये हड़तालें अंत में किसे हानि पहुंचाएगी। अधूरा ज्ञान सबसे बड़ी बुराइयों में से एक है। कुछ ज्ञान और निर्देश रूस से

प्राप्त करते है। हमारे कम्युनिस्ट इसी दयनीय हालत में जान पड़ते है। मै इसे शर्मनाक न कहकर दयनीय कहता हूं, क्योंकि मैं अनुभव करता हूं कि उन्हें दोष देने की बजाय उन पर तरस खाने की आवश्यकता है। ये लोग एकता को खंडित करनेवाली उस आग को हवा दे रहे हैं, जिन्हें अंग्रेज लगा लगा गए थे।"

भारतीय कम्युनिस्टों की बर्बरता

- 1979 . सुंदरबन द्वीप में पुलिस और माकपा कार्यकर्ताओं ने पूर्वी बंगाल के सैकड़ों शरणार्थियों को मौत के घाट उतार दिया।
- 1982 . माकपा कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में इस अंदेशे में 17 आनंदमार्गियों को जलाकर मार डाला कि निर्वाचन क्षेत्र में वे अपना आधार खो बैठेंगे।
- 2000 . भूमि विवाद को लेकर बीरभूमि जिले मे माकपा कार्यकर्ताओं ने कम से कम 11 भूमिहीन श्रमिकों की हत्या कर दी।
- 2001 . माकपा कार्यकर्ताओं ने तृणमूल कांग्रेस के प्रायोजित राज्यव्यापी बंद के दौरान मिदनापुर में 18 लोगों को मार डाला। (साभार– इंडिया टुडे, 28 नवंबर, 2007)
- 2007 . नंदीग्राम में अपना हक मांग रहे किसान, मजदूर और महिलाओं पर माकपा कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त जुल्म ढाए। महिलाओं के साथ बलात्कार किए। लाशों के ढेर लगा दिए। करीब 200 लोग मारे गए।

(संकलन : संजीव कुमार सिन्हा)

यह है भारत के छात्र.....

देश के सबसे बेहतर शिक्षा संस्थानों में से एक इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमैंट के छात्रों को आजकल विदेशों कंपनियों से ज्यादा देसी कंपनिया पसंद आ रही है। मैनेजमैंट के ये छात्र विदशों के आकर्शक ऑफरों के बजाय देश के विकास को ज्यादा महत्व दे रहे है। यह निश्चित तौर पर स्वागत योग्य पहल है, जिससे प्रतिभा पलायन को रोकने की दिशा में एक सकारात्मक संदेश के तौर पर देखा जा सकता है। दिल्ली के आदित्य कुमार आईआईएम–कोलकत्ता से अपनी मैनेजमैंट की पढ़ाई कर रहे है। अपने दोस्तो की तरह अगर वह चाहते तो अपनी समर प्लेसमैंट के दौरान किसी विदेशी कंपनी का हाथ थाम कर विदेश जा सकते थे, लेकिन इस दौरान कुमार ने नार्थ–ईस्ट भारत में कार्यरत एक गैर सरकारी संस्था के साथ जुडने का फैसला किया। गौरतलब है कि यह समर प्लेसमैंट आईआईएम छात्रों के भविश्य निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और छात्र इस दो महीने के समय में दस लाख रुपये तक कमा लेते है। आदित्य के पिता एक आईपीएस अधिकारी है और नार्थ–ईस्ट में उनके पिता के कार्यरत होने के दौरान उनको क्षेत्र की समस्याओं से रुबरु होने का मौका मिला। जिसे बाद आदित्य ने इस क्षेत्र के लिए कुछ करने का फैसला किया। आदित्य के लिए इन लोगों के बीच जाकर काम करने का अनुभव काफी अच्छा रहा और वह भविष्य में भी इन लोगों की समस्याओं के जुडे रहने का मन बना चुके है।

मैनेजमैंट संस्थान भी इस बात को मानते है कि हाल के कुछ समय में विदेश जाने वाले छात्रों और कैंपस प्लेसमैंट को लेकर छात्रों के उत्साह में कमी देखी गयी है। आईआईएम अहमदाबाद मे 2006–08 के बैच में दाखिला लेने वाले तकरीबन ग्यारह छात्र ने पहले ही कैंपस प्लेसमैंट से अलग रहने का मन बना लिया है। पिछले साल यह संख्या छ: रही थी। छात्र भी इस बात की तसदीक करते है कि आईआईएम जैसे संस्थानो से अपनी पढाई पूरी करने के बाद आजकल ज्यादातर छात्र आकर्शित विदेशी अवसरो को छोडकर इएंटरप्रोनर बनाना चहाते है।

हाल के सालों में भी छात्रो में इएंटरप्रोनर बनने के लिए उत्साह देखा गया है। साल 2006 में आईआईएम–मुम्बई के इलैक्टिकल इंजिनियरिंग के 35 छात्रों में से 27 ने इएंटरप्रोनर बनने की इच्छा जताई। इनोवीटी कम्पनी के सीईओ राजीव अग्रवाल बताते है कि साल 1990 के आसपास आईआईएम के 90फीसदी छात्र विदशी कम्पनियों के साथ ही अपना कैरियर शुरु करना चहाते थे, लेकिन हाल ही के कुछ समय मे इस ट्रेंड में बदलाव देखा गया है और छात्र इएंटरप्रोनर बनने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे है। साथ ही इनमें से कई छात्र तो मौजूदा कम्पनियो के आफॅर पैकेज से दुगना कमा लेते है। ऐसे मे कहना गलत नही होगा कि आज के नौजवान एक नई सोच के साथ देश के विकास मे अपनी एक अलग भूमिका तलाश करने का प्रयास कर रहा है। ■

तीन वर्षों में 16 हजार छात्रों ने की आत्महत्या

– उमाशंकर मिश्र –

हाल ही में 16 हजार छात्रों की गत तीन वर्षो के दौरान की गई आत्महत्या की खबर सुर्खियों में रही। उल्लेखनीय है कि अभी हाल ही में स्वास्थय मंत्रालय ने इस बात को स्वीकारते हुए देश में मानसिक स्वास्थय सेवाओं में कमी की बात को माना है। मंत्रालय के मुताबिक वर्ष 2006 में 5,857 छात्रों ने आत्महत्या की, जबकि 2005 में यह आंकडा 5,138 था, वहीं 2004 में 5,610 छात्रो की आत्महत्या के मामले प्रकाश में आए। स्वास्थय मंत्री अंबुमणि रामदास इस तरह की स्थिति को मानसिक स्वास्थय से जोड़कर देखते है और इसी के चलते राष्टीय स्वास्थय को नए सिरे से अमल में लाने की पहल कर रहे है।

प्रतियोगिता के दबाव, तनाव, चिडचिडापन और परीक्षा प्रणाली की खामियों के चलते छात्रों को मानसिक परेशानी झेलनी पड़ती हैं। ऐसे में फीस वृद्धि जैसी कवायदों से आग में घी का काम किया है। इस तरह के प्रशनों को अक्सर दरकिनार कर दिया जाता है, जबकि वास्तविक तौर पर यही विषय है, जिसके कारण जीवन के प्रति छात्रों निराशा बढ जाती है और ये आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हो जाते है। आज भी भारत करीब 24 प्रतिशत परिवार गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने को विवश है। ऐंसे में उनके लिए शिक्षा की अपेक्षा भोजन जुटाना ज्यादा अहम होता है। दूसरी ओर एक बहुत बड़ा वर्ग है, जो जीवन यापन के लिए संर्घषरत रहता है। इस वर्ग के छात्रों में ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर निर्भाय की ललक अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि उनके पास रोजगार अथवा धनोपार्जन के अन्य वैकल्पिक साधन जुटा पाना इतना सरल नहीं होता। लेकिन यह विडंबना ही है कि भारत जैसा देश जिसका संविधान समतावाद के सिद्धांत पर आधारित है; वहां की लोकतांत्रिक पद्धति से चुनी गई सरकार छात्र हितों को उपेक्षित करते हुए प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों में निरंतर फीस वृद्धि करते हुए गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा से दूर करने पर तुली हुई है। यही नहीं उच्च शिक्षा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भी आमंत्रित किया जा रहा है। जिसका सीधा असर भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर पड़ना लाजमी है। गरीब छात्रों की उच्च शिक्षा प्राप्त करने की लालसा ऐसे में धराशायी हो जाती है और जीवन के प्रति उनका नैराश्य बढ़ जाता है, जिससे वे आत्महत्या जैसा जघन्य अपराध कर बैठते हैं। सरकार इस तरह की घटनाओं को मानसिक बीमारी बताकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकती, क्योंकि शिक्षा जैसा विषय व्यावसाय की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, अपितु यह तो चैरिटी का विषय है। सरकार का यह दायित्व बनता है कि छात्र चाहे वह उच्च वर्ग का हो, मध्यम वर्ग का अथवा गरीब तबके का सभी को शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। लेकिन यह विडंबना है कि आजादी के 60 वर्षों का सफर तय करने के बाद भी इस मूलभूत अधिकार को जनाधिकार नहीं बना पाए हैं। आज शिक्षा का स्वरूप भी जाति, वर्ग एवं आंचलिक स्तर पर भिन्न देखने को मिलता है। वर्तमान आधुनिक युग में शिक्षा पर वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ा है, प्रतियोगिता भी बढ़ी है। ऐसे में महंगी शिक्षा और शैक्षिक संसाधनों की अनुपलब्धता छात्रों को मानसिक तौर पर झकझोर देती है। गौरतलब है कि इस झंझावात का ईलाज अंबुममिण रामदास भी नहीं कर सकते। फिर थोथी बयानबाजी करके राष्ट्र को गुमराह करने की स्वास्थ्य मंत्री की कवायद को शर्मनाक ही माना जाएगा। एक तरफ तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़कर शिक्षा को बनिये की दुकान पर बिकने वाला उत्पाद बनाने पर तुला हुआ है, तो दूसरी ओर सरकार का एक अन्य विभाग छात्रों की आत्महत्या को मानसिक बीमारी बताकर इस पर लीपापोती करने में जुटा हुआ है। इस तरह की कवायदों को समझना होगा कि किस तरह से एक सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय शिक्षा व्यवस्था को बाजार में बिकने वाली वस्तु के रूप में स्थापित किया जा रहा है। ■

राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रारित प्रस्ताव

प्रस्ताव–3

अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास समस्या

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अनुसूचित जाति जनजाति छात्र–छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु हमेशा संघर्षरत रही है। विद्यार्थी परिषद संवैधानिक व्यवस्थ में वर्णित रोटी, कपडा और मकान के आग्रह तक ही सीमित नही रहा, बल्कि परिषद ने संवैधानिक अधिकार शिक्षा और स्वास्थ्य को भी सामाजिक पटल पर आगे बढ़ाने मे अपनी पूर्ण भूमिका का निवर्हन किया है। आज भारत की आजादी के 60 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन इन 60 वर्षों मे सामाजिक विकास की योजना का लाभ समाज के अगले व्यक्ति को जितना मिला उतना अन्तिम व्यक्ति को नही मिल पाया है। समाज में असमानता दिख रही है । वर्ग भेद और जाति भेद सामने आ रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसे एक गम्भीर समस्या मानती है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा 16 राज्यों के 245 जिलों के कुल 1197 अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावासों का सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण द्वारा छात्रावासों के समस्या के बारे में जो जानकारी मिली है वह बहुत ही भयावह है। केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा विगत वर्षो से छात्रावासों के विकास के लिए जो योजना बनाई गई वह जमीनी धरातल पर उतरी ही नहीं। जिला कल्याण पदाधिकारी का निरीक्षण प्रवास नही होने के कारण छात्रावास मे रहने वाले छात्र–छात्राएँ अनाथ महसूस करते हैं। प्रीमैट्रिक से लेकर पी.जी. तक के छात्रों को छात्रवृत्ति कितनी मिलती है, मालूम ही नही है। छात्रावास विकास के लिए जो राशि केन्द्र सरकार द्वारा दी जाती है उसमें राज्य सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की जाती है या दूसरे विभाग मे खर्च कर दिया जाता है। भारत सरकार के महालेखा अधीक्षक के 2005–06 के अंकेक्षण प्रतिवेदन ;ब्।ळद्ध के अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनु. जाति जनजाति छात्र–छात्राओं के मे‍ ा प्रतिभा विकास योजना के मद मे भारत सरकार द्वारा दिये गये 23.8 लाख रूपये मे 17.19 लाख रूपये कर्मचारियों के वेतन मद मे भुगतान किया। महालेखाकार अंकेक्षण प्रतिवेदन के ही अनुसार असम सरकार ने 10.67 लाख, हरियाणा 10.87 लाख, तमिलनाडु 25.64 लाख और उ.प्र. सरकार ने 242.69 लाख रूपये केन्द्र सरकार से प्राप्त किये और उक्त राशि को छात्रवृत्ति वितरण के बदले राजस्व खाते मे डाल दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राज्य सरकारों द्वारा किये गये ऐसे गलत कार्य को दुर्भाग्यपूर्ण मानती है।

छात्रावास में प्रवेश प्रक्रिया हेतु पारदर्शिता का घोर अभाव है। कमरे कम रहने के कारण छात्र–छात्राएँ क्षमता से अधिक रहने को विवश होते हैं। पूरे देश के सभी अनु. जाति जनजाति छात्रावासों मे क्षमता से अधिक छात्र आज रह रहे हैं। झारखण्ड के चाईवासा महिला कॉलेज छात्रावास मे केवल 100 छात्राओं के रहने की क्षमता है लेकिन 334 छात्राएँ छात्रावास मे रह रही हैं। उसी प्रकार कर्नाटक के चामराजनगर मे छात्रावास में केवल एक कमरे में 150 छात्र रहते हैं। छात्रावास में शौचालय, पानी, बिजली का घोर अभाव है। कर्नाटक के सिदलहट्टा में 300 छात्रों के लिए केवल एक स्नानागार तथा एक शौचालय है। अनु.जाति जनजाति छात्र–छात्राओं के स्वास्थ्य की व्यवस्था मृगमरीचिका की तरह है। भोजन की व्यवस्था ठीक नही रहने के कारण छात्र–छात्राएँ विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित रहती हैं । इस संचार युग मे छात्रावास संचार विहीन है ।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस 53वें राष्ट्रीय अधिवेशन के माध्यम से केन्द्र तथा राज्य सरकारों से निम्न माँग करती है :–

छात्रावास प्रवेश

1. छात्रावास में प्रवेश प्रक्रिया सरल तथा भ्रष्टाचार मुक्त बनायी जाये।
2. महाविद्यालय तथा छात्रावास मे नामांकन एक ही समय किया जाये तथा इसे पारदर्शी बनाया जाये।
3. जनजातीय छात्र–छात्राओं का प्रवेश तथा शिक्षा निःशुल्क हो। पहले शुल्क लेना तथा बाद में प्रतिपूर्ति करने की जटिल व्यवस्था समाप्त की जाये।

छात्रावास व्यवस्था

4. अनुसूचित जाति जनजाति छात्र–छात्राओं के रहने हेतु पर्याप्त छात्रावास, भवन, कमरे, पानी, बिजली की व्यवस्था

सुनिश्चित की जाये।

5. सभी छात्रावासों में प्रत्येक आठ छात्र–छात्राओं पर एक शौचालय तथा एक स्नानागार बनाया जाये।

6. छात्रावासों के नियम रख–रखाव की व्यवस्था अनिवार्य की जायें तथा जर्जर हो चुके छात्रावासों का पुनर्निर्माण तुरन्त किया जाये।

7. नियमित पढ़ने वाले छात्रों और पढ़ाई पूर्ण करने के बाद तैयारी करने वाले छात्रों के लिए दो अलग–अलग छात्रावासों का निर्माण किया जाये।

सरकारी योजनायें

8. छात्रावासों में रहने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्र–छात्राओं को केन्द्र तथा राज्य सरकार की योजनाओं की सही–सही जानकारी दी जाये।

9. अनुसूचित जाति–जनजाति छात्र–छात्राओं की छात्रवृत्ति मूल्य सूचकांक के आधार पर तथा समय से मिलनी चाहिये । इस हेतु छात्र–छात्राओं का biodata कम्प्यूटरीकृत हो तथा Id-Card दिया जाये

10. जाति प्रमाण पत्र, उच्च विद्यालय (High School) पास करने के बाद विद्यालय परित्याग प्रमाण–पत्र के साथ तुरन्त दिया जाये तथा जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र बनाने में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर किया जाये। स्वास्थ्य/आरोग्य

11. छात्रावासों में रहने वाले छात्र–छात्राओं के स्वास्थ्य परीक्षण छात्रावास में ही नियमित किया जाये तथा प्रत्येक छात्रावास में थ्तेज ।पक ठवग रखा जाये।

12. प्रत्येक छात्रावास में महीने में दो बार सरकारी डॉक्टर को भेजने की व्यवस्था की जाये।

13. सरकारी अस्पतालों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्र–छात्राओं का इलाज निःशुल्क किया जाये।

शैक्षणिक सुविधाऐं

14. अनुसूचित जाति जनजाति छात्र–छात्राओं के लिये छात्रावासों में निःशुल्क अतिरिक्त कक्षा तथा च्ैब्ए च्ब्ै विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिये विशेष निःशुल्क कोचिंग की आवासीय व्यवस्था की जाये।

15. IT, Computer Education , Educational Counseling, General Counseling, Career Guidance, Employment Information Center आदि की व्यवस्था प्रत्येक अनुसूचित जाति जनजाति छात्र छात्राओं के छात्रावास में किया जाये।

16. औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र (I.T.I.) जैसी योजनाओं के तहत स्थानीय साधन, उनके उपयोग तथा तकनीकी प्रशिक्षण सम्बन्धी पाठ्यक्रम जनजातीय क्षत्रों में चलाया जाये। जैसे : कृषि, वानिकी, वनोत्पाद, औषधि वनस्पति एवं परम्परागत चिकित्सा का ज्ञान आदि।

अन्य सुविधाऐं

17. अनुसूचित जाति जनजाति छात्रवासों में सुरक्षा, मनोरंजन, लोककला, लोकगीत, लोकसंगीत तथा खेलकूद की समुचित व्यवस्था की जाये।

18. दूरदर्शन, पत्र–पत्रिका, पुस्तकालय तथा पुस्तकों की व्यवस्था सभी छात्रावासों में की जाये।

19. सभी छात्रवासों में फोन (Coin Box) की व्यवस्था की जाये।

अन्य गतिविधियाँ

20. अनुसूचित जाति जनजाति विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और स्वाभिमान उत्पन्न करने हेतु पाठ्यक्रमों में जनजातीय महापुरूषों के प्रेरणापद जीवन परिचय एवं सांस्कृतिक विरासत का अध्ययन सम्मिलित किय जाये।

21. जनजातीय शिल्प कला को प्रोत्साहित करने हेतु जनजातीय बहुल राज्यों के विश्वविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाये।

22. प्रतिवर्ष सम्बन्धित प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जनजातीय बहुल क्षेत्रों में वार्षिक क्रीडा, सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं को जनजातीय महोत्सव के रूप में मनाया जाये।

नीति एवं व्यवस्था सम्बन्धी

23. छात्रावास अधीक्षक का आवास छात्रावास में ही हो तथा कर्मचारियों के रिक्त पदों को अविलम्ब भरा जाये।

24. पूरे देश के सभी राज्यों में महाराष्ट्र छात्रावास पद्धति को लागू किया जाये।

25. जिला कल्याण पदाधिकारी तथा Integrated Tribal Development Project Officer (समेकित जनजातीय विकास परियोजना पदाधिकारी) नियमित छात्रावासों का निरीक्षण करें।

26. विभिन्न जनजातीय सरकारी पदों के बहाली हेतु विशेष रोजगार भर्ती मेला जैसे प्रयास हों एवं शिक्षा क्षेत्र में छात्र कल्याण नीति घोषित की जाये।

■

प्रस्ताव – 4

श्रीराम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का यह 53वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन करोड़ो भारतीयों की आस्था एवं अस्मिता की पहचान श्री राम सेतु केन्द्र सरकार द्वारा तोडे जाने के प्रयास की कड़ी भर्त्सना करता है । श्री राम सेतु हमारी राष्ट्रीय विरासत, संस्कृति, आस्था एवं पहचान का आधार तथा ऊर्जा का स्त्रोत है । केन्द्र सरकार के अभिकरण भारतीय पुरात्त्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) ने 11 दिसम्बर, 2007 को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत शपथ पत्र में भगवान राम के अस्तित्व को ही नकार दिया । अधिवेशन का यह सुविचारित मत है कि भगवान राम व राम सेतु को नकारना भारत के इतिहास, भूगोल के साथ–साथ हमारी श्रद्धा व सांस्कृतिक चेतना पर आघात को भारतीय जनमानस सहन नही करेगा ।

अ.भा.वि.प. का यह अधिवेशन उपरोक्त राष्ट्र विरोधी निर्णय के लिये जिम्मेदार केन्द्र सरकार, श्रीमती सोनिया गाँधी, श्री करूणानिधि, श्री टी.आर. बालू व इनके इशारे पर काम करने वाली ए.एस.आई. जैसे अभिकरणों को यह एहसास दिलाना चाहता है कि राम इस देश की सांस्कृतिक पहचान है । केन्द्र सरकार के निर्देश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) द्वारा राम के अस्तित्व को नकारने वाला शपथ पत्र दायर किया जाना यह दर्शाता है कि केन्द्र सरकार जानबूझकर राष्ट्रीय स्वाभिमान पर चोट कर रही है ।

अ.भा.वि.प. का मानना है कि सरकार को समाज के श्रद्धा और आस्था के विषय तय करने का कोई हक नही है अपितु जनता की जनभावना का संरक्षण करना सरकार का दायित्व है । परन्तु दुर्भाग्य से वामपंथियों के कंधों पर टिकी व सोनिया गाँधी के इशारों पर चलने वाली वर्तमान केन्द्र सरकार कभी एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकों में महापुरूषों का अपमान करती है, तो कभी भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी को संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में आतंकवादी बताती है । हद तो तब हो गई जब केन्द्र सरकार के अभिकरण ए.एस.आई. ने भगवान राम के अस्तित्व को ही नकार दिया। अभाविप का यह 53वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन केन्द्र सरकार से मांग करता है कि वह अपने इस कृत्य के लिए देश से माफी मांगे । अभविप केन्द्र सरकार का ध्यान 1993 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ के न्यायमूर्ति तिलहरी व गुप्ता द्वारा श्री राम जन्मभूमि सम्बन्धित सबन्धित एक मामले में दिये गये निर्णय की ओर दिलाता चाहती है जिसके अनुसार श्री रामचन्द का इतिहास, परम्परा, मान्यता, आस्था व धर्म ग्रन्थों के आधार के साथ–साथ एक संवैधानिक अस्तित्व भी है । श्री राम के अस्तित्व को नकारने का एक अर्थ इक्ष्वाकुवंशीय तथागत बुद्ध, सभी तीर्थीकरों सहित भगवान महावीर, आदि कवि वाल्मिकी, गुरू नानक देव व गुरू गोविन्द सिंह जी के इतिहस को नकारना भी है ।

अभाविप का स्पष्ट मानना है कि राम सेतु जहाँ हमारी आस्था का विषय है वहीं इसके साथ अन्य महत्व प्रश्न भी जुड़े हैं जिनका जवाब केन्द्र सरकार के पास नही है । सेतु समुद्रम नहर परियोजना को लागू करने से पूर्व राम सेतु तोड़ने से होने वाले प्रभावों का कोई अध्ययन नही किया गया, किसी विशेषज्ञ से भी सलाह नही ली गई । फिर भी लाखों वर्षों से वहाँ मौजूद थोरियम, पर्यावरण, सुनामी, जैवविविधता, तटीय प्रदेशों के जीवन, लाखों मछुआरों की आजीविका व सामरिक महत्व जैसे मुद्दों पर भी केन्द्र सरकार ने देश को गुमराह किया है । केन्द्रीय मंत्री श्री टी.आर. बालू व केन्द्र सरकार सेतु समुद्रम परियोजना को देश के विकास के नाम पर लागू करना चाहते हैं । विद्यार्थी परिषद विकास कार्ययोजनाओं का स्वागत करती है किन्तु इस परियोजना में विकास का नारा भी खोखला सिद्ध हो रहा है । इस परियोजना पर कुल 2227 करोड रूपये खर्च होंगे परन्तु योजना पूर्ण हाने पर यह राशि कहाँ से मिलेगी ? प्रतिवर्ष रख–रखाव पर जो भारी खर्च आएगा, नहर बनने पर जहाजों के वजन वाहक क्षमता में कमी आएगी, इतना ही नही 10 लाख मछुआरे अपनी–अपनी आजीविका खो देंगे, जिसका अर्थ विकास नहीं विनाश होगा । अधिवेशन का यह मानना है राम सेतु का नष्ट करने से जहाँ सुनामी के खतरे बढ़ेंगे वही भारत की तटीय सुरक्षा के लिये भी खतरे बढ़ेंगे । नये जलमार्ग बनने से भारत और श्रीलंका के मध्य की सीमा को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मानकर अन्तर्राष्ट्रीय जलयान यहाँ से गुजरेंगे जिस से भारत की तटीय सुरक्षा पर दबाव बढ़ेगा । जहाँ एक ओर सरकार परमाणु करार के लिए सर्वथा प्रयासरत है। वही राम सेतु क्षेत्र में उपलब्ध 3 लाख 30 हजार टन थोरियम को आखिर किस षडयंत्र के तहत नष्ट करने पर तुली है? वैज्ञानिकों का मत है कि थोरियम का यह भण्डार कम से

कम तीन शताब्दी तक देश को ऊर्जा प्रदान कर सकता है । राम सेतु को तोड़ने से अनुमानतः मन्नार की खाड़ी में जीव–जन्तुओं व पौधों की 3600 प्रजातियाँ तथा मछलियों की 600 प्रजातियाँ नष्ट हो जाएगी जिससे जलीय पर्यावरण असंतुलित होगा। खुदाई से उत्पन्न कचरे से भी समुद्र में पर्यावरण प्रदूषित होगा ।

अ.भा.वि.प. का यह अधिवेशन केन्द्र सरकार से माँग करता है कि राम सेतु के पौराणिक, ऐतिहासिक, सामरिक, जैवविविधता जैसे महत्व को ध्यान में रखते हुए, प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1959 की धारा 4 (1) के अधीन श्री राम सेतु को प्राचीन धरोहर व राष्ट्रीय स्मारक घोषित करे ।

अ.भा.वि.प. का 53वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन अपनी पूरी शक्ति के साथ यह संकल्प लेता है कि वह उन सभी लोगों को जो रामसेतु तोड़ने के इस राष्ट्र विरोधी निर्णय के लिये जिम्मेदार है तथा जो उनका संरक्षण दे रहे हैं, को कभी माफ नही करेगा । अ.भा.वि.प. देश की छात्र–युवाशक्ति से यह अपील करती है कि वह रामेश्वरम् रामसेतु रक्षामंच द्वारा छेड़े गये व्यापक आंदोलन को तन मन धन से सहयोग कर सरकार के श्रीरामसेतु तोड़ने का प्रयास को विफल करें । ■

आईआईएम–आईआईटी में फीस वृद्धि प्रतिभाशाली गरीब छात्र प्रतिस्पर्धा से बाहर

– आशीष कुमार 'अंशु' –

देश के प्रतिष्ठित आईआईटी, आईआईएम सरीखे शिक्षा संस्थान पिछले दिनों काफी चर्चा में रहे। वजह थी, फीस बढ़ोत्तरी की मांग। यह फीस बढ़ोतरी भी कुछ रुपयो की नहीं थी, बल्कि वृद्धि दुगुनी–तीन गुनी करनी थी। इसका अर्थ यही निकलता है ना कि इन संस्थानों को प्रतिभाशील छात्रों की नहीं बल्कि पैसे वाले छात्रों की अधिक जरूरत है। या फिर यह संस्थान मानती है कि तुम पैसा दो और हम तुम्हें होनहार बना देंगे। अहमदाबाद, बैंगलौर, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर और कोजीकोडे स्थित आईआइएम संस्थान प्रबंधन ने तय किया है कि शैक्षिक सत्र 2008–10 में स्नातकोत्तर की शिक्षा लेने आने वाले छात्रों की फीस बढ़ाई जाएगी। आईआईएम के इस पहल के बाद आईआईटी कैसे पीछे रहता, उसने भी फीस वृद्धि की घोषणा कर दी।

इस फीस बढ़ोत्तरी से वे छात्र जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि सुदृढ नही है, वे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिए जाएंगे। मानव संसाधन मंत्री ने राज्य सभा में कहा कि स्टैंडिंग कमिटी ऑफ आईआईटी काउन्सिल (एससीआईसी) ने फीस वृद्धि की अनुशंसा की है।फीस वृद्धि से होने वाले नुक्सान हमें सीधे तौर पर नजर नहीं आ रहे हैं लेकिन यदि हम थोड़ा विचार करें तो स्थिति स्पष्ट होते देर नहीं लगेगी। आज हमारे यहां शोध की हालत कीतनी बूरी है, यह बात किसी से छुपी नहीं है। कोई छात्र अपनी पढ़ाई लंबे समय तक जारी नहीं रखना चाहते है। इसकी एक मुख्य वजह महंगी होती शिक्षा है। किसी विषय में शोध करते हुए अधिक समय बिताने वाले छात्र की आर्थिक सुरक्षा की जमानत ना समाज देता है, ना सरकार देती है। इसलिए जो लोग आर्थिक तौर पर सुदृढ़ परिवार से ताल्लुक रखते हैं, शोध जैसे विषय ऐसे ही छात्रों के शगल बन गए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्राध्यापक ने बताया कि आज तमाम विश्वविद्यालयों में शोध सिर्फ छात्र लेक्चरार या रीडर बनने के लिए कर रहे हैं। देश के कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के पास इस बात का कोई रिकार्ड नही है कि उनके यहां किस–किस विषय पर शोध हो चुके हैं। भारत अपनी जीडीपी का सिर्फ 0.81 प्रतिशत शोध पर खर्च करता है। बल्कि अन्य देशों में यह औसत जीडीपी का 1.91 प्रतिशत है। चीन इसके लिए 2.62 प्रतिशत खर्च करता है।

जो बच्चे बड़े संस्थानों में पढ़ने के लिए लाखों रुपए खर्च करेंगे, उनसे हम कैसे उम्मीद करेंगे कि वे आगे चलकर अधिक आमदनी के लिए नहीं सोचकर, देश और समाज की तरक्की के लिए, विकास के लिए सोचे। सबसे बुरा उन बच्चों के साथ होगा, जो योग्यता होने के बावजूद सिर्फ पर्याप्त धनराशि नहीं होने की वजह संस्थान में दाखिले से वंचित रह जाएंगे। सरकार की देखरेख में चलने वाली इन संस्थानों में कम से कम उन बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए, जो योग्य है लेकिन जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं है कि वे फीस में इतनी मोटी रकम दे पाएं। यदि सरकार ऐसी कोई व्यवस्था कर पाती है तो हम विश्वास कर सकते हैं कि इस तरह आईआईएम और आईआईटी से कुछ ऐसे और छात्र सामने आएंगे जो अपने जैसे अन्य छात्रों और देश–समाज के लिए कुछ सार्थक प्रयास करेंगे। ■

OBITUARY

Smt. Nirmala Deshpande

Widely respected Gandhian and a recipient of Padma Vibhushan, Nirmala Deshpande died on 1st May at the age of 79. She was an eminent freedom fighter and social worker. Nirmala Deshpande shot into fame in 1952, when she walked with Vinoba Bhave in the 'Bhoodan' movement. She undertook 40,000-km padhyatra across India to carry Mahatma Gandhi's message of Gram Swaraj. She firmly believed that although it was difficult to practice Gandhian principles, it was the only way towards a truly democratic society.

Nirmala Deshpande worked hard for the empowerment of women, promotion of communal harmony and rural development. She always served the country with distinction. Nirmala Deshpande was perhaps the last leader to promote Gandhian values of simplicity, decency and honesty.

Deshpande was born in Nagpur on October 19, 1929, and completed her education there. She was also a Rajya Sabha member since 1997 and her name was considered briefly for the President's post and for the Nobel peace prize in 2005.

Deshpande was also known to be the spirit behind the peace marches in Punjab and Kashmir when violence was at its peak in these regions and the social fabric was being torn asunder. Her peace mission to Kashmir in 1994 and her initiative to organise India-Pakistan meet in 1996 were some of her major achievements in her decade of public service. The Tibetan cause, too, was close to her heart.

Students need health education, not sex education-Atul Kothari

National co-convener of Shiksha Bachao Andolan Samiti Shri Atul Kothari said the students in the country need health education and not sex education. "It is wrong to say that people are dying only due to AIDS. They are also dying due to various other diseases like cholera, diarrhoea, malaria and tuberculosis. Our government has not given much importance and publicity for eradication of these diseases. It is thinking more about AIDS and spending more money on this. There is no mechanism to study the aftermath of the introduction of sex education among the students," he said.

Shri Kothari was speaking at a function held at Visakhapatnam by Vidya Samrakshana Samiti on April 24.Shri Kothari further said the Government of India is thinking against the traditional system of the country and is giving wide publicity to condoms blindly following the dictates of UNO. He said it would deteriorate the relationship between guru and shishya. "The moral values have already come down due to obscenity in movies and television channels. Today, everybody wants moral values in education. Even in foreign countries yoga is given priority in schools and colleges, but in our own country it is neglected," he said. He appealed to the government to think of eradicating different disease instead of wasting time and money over AIDS. He also appealed to the people of the country to oppose the vicious designs of foreign countries, which are trying to uproot our age-old Indian family system.

लाल बादशाह का 'कुजन' पर कोप

वैचारिक मंझधार और सत्ता की चाशनी में फंसे कामरेडों की बौखलाहट

आलोक मेहता

[संपादक, आउटलुक साप्ताहिक]

दिल्ली में हमारे प्रगतिशील मित्र गुजरात, उड़ीसा, छत्तीसगढ, जम्मू–कश्मीर जैसे राज्यों में सांप्रदायिक तनाव अथवा नागरिकों पर उत्पीड़न के गंभीर मुद्दों पर पूरे जोर–शोर के साथ प्रबुद्ध लोगों की छानबीन कमेटी, सदभावना दल भेजे जाने पर जोर देते हैं । छत्तीसगढ़ में बिनायक सेन की मुक्ति के लिए नोबेल पुरस्कार विजेताओं की अपील लेकर दौड़धूप हो रही है । दूसरी तरफ, पिछले शनिवार– रविवार कोलकत्ता यात्रा के दौरान 'प्रगतिशीलता' का दावा करने वाली मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रादेशिक सचिव बिमान बोस को टी.वी. चैनलों पर गरजते हुए सुना । 'क्रांतिदर्शी' बोस साहब बरसे, 'राज्य चुनाव आयोग ने प्रसिद्ध अभिनेत्री अपर्णा सेन तथ अन्य बुद्धिजीवियों को पंचायत चुनाव के दौरान नंदीग्राम जाने की इजाजत क्यों और कैसे दी? ये सब 'कुजन' (हिंदी में दुर्जन) है और सभी 'सुजन' (सज्जन) नागरिकों का दायित्व है कि उन्हें रोकें । अपर्णा सेन के साथ नंदीग्राम जाने वाले प्रतिनिधियों में थिएटर की हस्ती शोनाली मित्रा और कौशिक सेन एवं पेंटर शुभप्रसन्ना शामिल थे । वे पंचायत–चुनाव में कम्युनिस्टों की दादागिरी, ज्यादतियों और हेराफेरी के आरोपों की छानबीन के लिए निहत्थे जा रहे थे । इनमें से किसी का निहित राजनीतिक स्वार्थ नही था। बोस साहब का कहना है कि पश्चिम बंगाल पंचायत–चुनाव कानून के अंतर्गत ऐसे पर्यवेक्षकों के जाने का कोई प्रावधान नही है । कितना अजीब हास्यास्पद तर्क है । पश्चिम बंगाल के पितृ–पुरूष माने जाने वाले बिधानचन्द्र राय बरसों पहले यह कल्पना कैसे कर सकते थे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और रवींद्रनाथ टैगोर की बंग भूमि में ऐसे अराजक तत्वों का वर्चस्व हो जाएगा जो गांवों के गरीब निरीह ग्रामीणों को अपनी इच्छा से पंच चुनने की व्यवस्था को बंदूक की नोक से संचालित करेंगे। इस समय पश्चिम बंगाल में पंचायतों और जिला परिषदों के करीब 51 हजार प्रतिनिधियों को चुनने का अवसर 5 साल बाद आया है । कामरेड लोगों ने 2003 में लगभग 38 हजार सीटों पर कब्जा किया था । बड़ी संख्या में लोग उनकी मनमानियों और ज्यादतियों से तंग हैं। बदलाव भी चाहते हैं लेकिन कोलकाता में कार्यरत कुछ तटस्थ अधिकारी भी मानते हैं कि कई स्थानों पर मतदाताओं को डराने–धमकाने के साथ उनके वोटर कार्ड और मत–पत्र तक छीन लिए गए। कम्युनिस्टों के दबाव मे आखिरकार बुद्धिजीवियों की तटस्थ पर्यवेक्षक टीम को भी आधे रास्ते में रोक दिया गया । आश्चर्य यह है कि दिल्ली में बैठे प्रगतिशील मित्रों या नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने पश्चिम बंगाल के लाखों सामान्य नागरिकों के मूलभूत अधिकारों के हनन तथा जुल्मों के विरूद्ध कोई वक्तव्य जारी नही किया।

संभव है, बंगाल के गांव दिल्ली से बहुत दूर हैं । यों ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस तथा केन्द्र में राज कर रही कांग्रेस पार्टी के नेता बंगाल की बदहाली तथा पंचायत चुनाव की धांधली से अनजान नही हैं लेकिन उनके लिए कम्युनिस्टों की बैसाखी अपरिहार्य है । केन्द्र सरकार अपने ही सूचना प्रसारण मंत्री प्रियरंजन दासमुंशी के दुःखड़े 'स्थानीय राजनीति का लफड़ा' मानकर आंख मूंदकर बैठी रह सकती है । यह कोई नई बात नही है ।

बंगाल के पंचायत चुनाव में कम्युनिस्टों की मनमानी का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि मार्क्सवादी सांसद

ललित सेठ मोबाइल फोन पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के उप महानिदेशक आलोक राज और उनके सिपाहियों को अपने तंबू में चुपचाप बैठे रहने की चेतावनी दे रहे थे । सांसद और पुलिस अधिकारी का संवाद मोबाइल फोन की लाउडस्पीकर सुविधा के कारण पूरे देश में सुना जाता रहा। लेकिन दिल्ली में बैठे नेता भी मूकदर्शक बने रहे। गठबंधन की पंगु सरकार राज ठाकरे के भड़काऊ राष्ट्र विरोधी बयानों अथवा बंगाल के आतंकवादी की तरह व्यवहार कर रहे कम्युनिस्टों द्वारा कर्तव्यनिष्ठ केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारियों को धमकाने और बलात्कार के झूठे आरोपों में फंसाने के प्रयासों पर डाक से हफ्ते–दस दिन में पहुँचने वाली रिपोर्ट की प्रतीक्षा के अलावा क्या कर सकती है? अमेरिका या पाकिस्तान में दिये जाने बयानों पर तत्काल भड़कने वाले राष्ट्रीय नेताओं तथा 'जासूस' अफसरों को अपने ही देश में खुलेआम की जा रही ज्यादतियों के लिए लाल फीते से बंधी रिपोर्ट का इंतजार क्यों रहता है?

प्रजातंत्र के सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ पंचायत चुनाव को सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए ही केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की टीम पश्चिम बंगाल भेजी गई । हास्यास्पद स्थिति यह बनी कि राज्य प्रशासन ने सीआरपीएफ को असली तनाव–ग्रस्त इलाकों से दूर रहने के निर्देश तक दे दिए । ऐसी दादागिरी तो कभी बिहार या जम्मू–कश्मीर के नेताओं ने नहीं की । सीआरपीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी पर बलात्कार का झूठा आरोप मढ़ने की बात भी अगले दिन साबित हो गई, जब उसी महिला ने आलोक राज नाम के व्यक्ति को देखने या उसका नाम तक नहीं सुनने की बात कर दी, जिसके नाम पर कामरेडों ने बलात्कार की प्राथमिकी दर्ज करा दी थी । यही नहीं, सत्तारूढ़ माकपाई राज्यपाल गोपाल गांधी की मलामत से भी बाज नहीं आए जिन्होंने बिजली संकट को देखते हुए राजभवन में दो घंटे बिजली कटौती कर जनता के साथ विनम्र और मौन गांधीवादी एकजुटता जताई थी।

बंगाल के कम्युनिस्ट आजकल वैचारिक मंझधार और सत्ता की चाशनी में मक्खी की तह फंस गए हैं । वे लाल झंडा हाथ में रखकर उदारवादी आर्थिक नीतियों का क्रियान्वयन करना चाहते हैं । कोलकाता में अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों, कॉल सेन्टरों की गिनती बढ़ती जा रही है जिससे शिक्षित युवकों की जिंदगी बदली हुई नजर आ रही है । पार्टी समर्थकों को दिए गए ठेकों से सड़कें भी कुछ चमचमाने लगी हैं लेकिन राजधानी के बाहर अन्य जिलों में बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार और ज्यादतियों का बोलबाला है । जिन ग्राम पंचायतों पर कम्युनिस्टों का कब्जा रहा, वहां ग्रामीणों की स्थिति अधिक दयनीय हुई है । गरीब किसानों की जमीन उद्योगों के लिए अधिग्रहीत हो रही है । ऐसी स्थिति में नक्सलियों का प्रभाव बढ़ने लगा है । पंचायतों पर वर्चस्व हटने के खतरे से कम्युनिस्ट बौखला से गए क्योंकि कुछ महीनों बाद लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं । उनकी एकमात्र उम्मीद इस बात पर है कि कांग्रेस और भाजपा आज के सशक्त विकल्प नहीं बन पाई है । तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी के 'पलायनवाद' ने उनकी साख बहुत गिरा दी है इसलिए सत्ता के सिंहासन पर बैठे 'लाल बादशाह' लाठी–बंदूक की नोंक पर जयकार कराते रहने की कोशिश जारी रखेंगे । ■

राजधानी के बाहर अन्य जिलों में बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टचार और ज्यादतियों का बोलबाला है। जिन ग्राम पंचायतों पर कम्युनिस्टों का कब्जा रहा, वहां ग्रामीणों की स्थिति अधिक दयनीय हुई है । गरीब किसानों की जमीन उद्योगों के लिए अधिग्रहीत हो रही है। ऐसी स्थिति में नक्सलियों का प्रभाव बढ़ने लगा है। पंचायतों पर वर्चस्व हटने के खतरे से कम्युनिस्ट बौखला से गए क्योंकि कुछ महीनों बाद लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं।

(साभार : आउटलुक)

परिचर्चा

चीन, तिब्बत – भारत अंतर्संबंध

वीरेन्द्र चौधरी, पत्रकारिता छात्र

तुलसीदासजी ने रामचरित मानस में लिखा है, 'सबै सहाय सबल के, निर्बल कोउ न सहाय, पवन जलावत आग के, दीपही देत बुझाए।'

तिब्बत के साथ इन दिनों यही स्थिति है। चीन की ताकत से सभी देश आतंकित है। इसलिए चीन अपनी मनमर्जी कर रहा है। तिब्बत अपनी ताकत भारत को समझता रहा है। इस बार भारत भी टाल–माटोल कर रहा है। तिब्बत को लेकर उसका रूख क्या है, यह बहुत हद तक स्पष्ट नहीं है। यह स्थिति ठीक नहीं है।

इसी तरह तुलसीदास ने अपने एक अन्य दोहे में कहा है कि 'समरथ को नहीं दोष गोसाई।' इसलिए तिब्बत को इतनी कठीनाई का सामना करना पर रहा है। यदि तिब्बत समर्थवान होता, शक्तिशाली हो तो क्या चीन की हिम्मत थी कि तिब्बतियों को उनके अपने जमीन से बेदखल कर देता? भारत की सरकार को एक बार तय अवश्य करना चाहिए कि वह सच्चाई का साथ देना चाहती है या फिर 'सामर्थ्यवान चीन' का।

रजनीश,छात्र

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि भारत के लिए तिब्बत का मामला महत्वपूर्ण है। चूकि तिब्बत की तरह भारत भी चीन की विस्तारवादी निति का शिकार रहा है। चीन की चर्चा करते वक्त 1962 की लड़ाई को कैसे भूल सकते हैं। जब चीन ने हमें धोखा देकर हमारी अपनी जमीन हमसे छीन ली थी। एक बार धोखा खाने के बाद क्या हम फिर उसपर भरोसा करने की सोच रहे हैं, यदि ऐसा है तो यह हमारी मूर्खता है। अब चीन की नजर हमारे अरूणाचल प्रदेश पर भी है। उसने अपने सरकारी नक्शों में इसे अपने देश में दिखाया भी है। तिब्बत का मसला एक मौका हो सकता है, भारत के लिए। तिब्बतियों का साथ देकर भातर न्याय का साथ देगा। उसे तिब्बत के साथ खुलकर खड़े होना चाहिए।

रविशंकर, शोधार्थी

शांतिप्रिय और अहिंसक बौद्ध भिक्षुओं पर जिस तरह चीन साम्यवादी और जनवादी प्रयोग कर रहा है। उसपर भारत के बुद्धिजीवी वर्ग में एक खतरनाक किस्म की खामोशी तारी है। भारी संख्या में निरीह तीब्बती मारे जा रहे हैं। हैरत की बात यह है कि इसके खिलाफ सम्राज्यवादी माने जाने वाले अमेरिका ही दो शब्द कहा है, वरना हर तरफ शांति–शांति है।

पंचशील, पारस्परिक सदभाव और कश्मीर की स्वायतता के लिए अपने देश के हित तक को ताक पर रख देने वाले हमारे देश के मानवतावादी और सम्राज्यवादविरोधी बुद्धिजीवियों और नेताओं ने भी इसकी कोई जरूरत नहीं समझी। म लगातार मारे जा रहे तिब्बतियों की मौत को वे हत्या मानने को तैयार नहीं है। इस तरह की दोगली नीति पर चलने वाले लोग सिर्फ गाल बजाना जानते हैं। इस वक्त तिब्बत को मदद की जरूरत है और उसके मदद के लिए अवश्य आगे आना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है।

नितिन रवि, विधि छात्र

तिब्बत में चीन जिस तरह की दमनात्मक कार्यवाही कर रहा है, उसपर भारत की चुप्पी के लिए चीन ने भारत की सराहना की है। चीन के अनुसार भारत एक सच्चे पड़ोसी का कर्तव्य निभा रहा है। लेकिन भारत को नहीं भूलना चाहिए कि यह वहीं चीन है जिसने हमें 'हिन्दी चीनी भाई–भाई' का बहकावा देकर, हमारे पीठ पर खंजर डालने का काम किया था। तिब्बतियों के संबंध में यह बात पूरी दुनियां जानती है कि वे सदभाव और प्रेम को पसंद करने वाले सीधे लोग हैं। चीन ने जिस तरह से उनके साथ हिंसक बर्ताव किया है। वह क्षम्य नहीं होना चाहिए।

■

Delhi Fiddles While The Northeast Burns

- Tarun Vijay -

Visiting Nagaland makes you feel different. You have to procure an inner line permit to enter. The permit demands to know why I am going there, where I shall stay and to be sure about my credentials I needed a guaranteer to vouch for me, my safe conduct and return within the stated period. Issued by the deputy commissioner's office this permit is governed under the Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873. Yes, 1873.

The British left India in 1947. We are celebrating the 60th anniversary of that freedom obtained after our motherland's division and the massacres that followed. Still, I needed a permit, something that the British began to isolate these regions in the name of 'protecting' the local indigenous people. The same procedure is also in vogue in Arunachal Pradesh.

So, we, legitimate Indians, are required to obtain a permit -- another name for a 'visa' -- but these states are reeling under the heat of illegal Muslim infiltrators from Bangladesh, who, obviously do not need to get an permit to enter, buy land, marry local girls and become so dominant that even the state authorities feel afraid to oust them.

Arunachal Pradesh's student bodies recently compelled Chief Minister Dorjee Khandu to take action against the Bangladeshis. So what did he do? He pushed a couple of thousands to Assam and the matter ended. In Assam it created a furore. The Muslim bodies, specially the All Assam Minorities Students Union, threatened to oust Hindus from Muslim majority districts like Dhubri, Goalpara and Barpeta, so Assam Chief Minister Tarun Gogoi 'certified' that all those ousted by the Arunachal Pradesh government are Assamese and shall be accommodated in Barpeta!

The situation is so serious and Delhi's apathy so mindboggling that the people have lost all hope. The All Assam Students Union, which spearheaded an unprecedented movement in the 1980s to oust Bangladeshi infiltrators, has in utter desperation said that in the next ten years Assam may have a Bangladeshi chief minister. Strong and alarming words indeed. But neither the media nor the political parties paid any attention.

Assam has been transformed beyond recognition. The state's cultural identity is symbolised by the great reformer and rejuvenator Srimat Sankar Dev. His birthlace in Dhing, near Bardowa, is a must-visit pilgrim centre for every Assamese Hindu. Now the Dhing assembly

constituency has 90.02 percent Muslims. No prizes to guess how this Hindu pilgrim centre became a Muslim majority town because of the Bangladeshi influx.

Assam's latest political star is Maulana Badruddin Ajmal, a perfume tycoon, who formed a new political party, the United Democratic Front, in 2005 and won 10 seats in the 2006 assembly election, surprising everyone. Previously he used to remote control other secular parties. Now he has taken the reins in his hands.

Assam and other northeastern states have become more volatile than Kashmir, but Delhi's page three media and corrupt polity don't see beyond their immediate concerns.

After Assam and Arunachal Pradesh, it is Nagaland's turn now. Bangladeshi jihadi factories supplying men and material are creating havoc from Itanagar to Kohima and Hyderabad. They are there before everybody's eyes, yet no government has shown a steely resolve to identify them and send them back. Aliens are turned into voters for political gain. The lines dividing traitors and patriots are getting blurred. Patriotic people need permits, they are made to live a refugee's life, but aliens feel quite confident and vocal to aggressively enter our country, bomb it and yet find sympathies in the corridors of power.

In Nagaland, people are sandwiched between the insurgent groups and the Bangladeshi influx. The headquarters of the National Socialist Council of Nagaland (Issac-Muivah group) is in Hebron, 30 odd kilometres from Dimapur. Everywhere, while going to Kohima one can see posters demanding 'quick results of peace talks' and a greater Nagalim which they want in the name of Christ -- a separate independent country. According to government sources there are about 75,000 Bangladeshi Muslims in Nagaland today.

I had come to attend a seminar organised by a daring tribal organisation, the Janajati Vikas Samiti, which had invited about 80 participants from the northeastern states. Nagaland Home Minister Thenucho inaugurated the conference. Former state secretary C M Chang headed the organising committee. It was incredible to see so many tribal leaders engrossed in what can be termed a free discussion on the problems Nagaland faces -- Bangladeshi infiltration being the foremost.

Minister Thenucho was forthcoming and said this problem has to be seen as a demographic invasion. 'The Naga people may be soon reduced to miserable sufferers by these infiltrators, who may appear as an asset for providing cheap labour and easily available hands for menial jobs. But look what they have done elsewhere and there is no guarantee that they will not do the same here. Today they work as labourers; tomorrow Nagas will have to work for them, if we do not stand up and say no to them,' the minister said. He was serious.

The only problem is the Centre does not share their anxieties. Nothing that binds Naga society with the rest of the country has ever been encouraged and strengthened. Natwar Thakkar started his Gandhi ashram in Mokukchang but could never expand his mission of spreading Gandhi's sublime thoughts beyond that.

To be in Kohima is still considered a matter of fear, pregnant with life and death questions. There is no icon of India that can be seen here. In the early 1980s a Gandhi statue was installed in Kohima, only to be desecrated and destroyed soon. 'Nagaland doesn't need any Indian's statue' was the decree issued by the insurgents.

Almost everyone, from IAS officers to traders and teachers, have to cough up a part of their earnings to the insurgents. Their 'freedom days', 'republic days' are celebrated in full public view with the media from Kolkata and Delhi in attendance. Presently there is a ceasefire between the NSCN (IM) and the Indian Army, but rumours

are afloat that this period has been better utilised by the insurgents to reinforce its battalions with new recruits, procure better weapons and resources to press for its demand for an 'independent 'Nagalim', which seeks to 'add' parts of Manipur and Arunachal Pradesh to its fold.

This has enraged Manipuri and Arunachali tribals and a tribal war cannot be ruled out if the Naga insurgents' demand is given any sympathy.

The press is lively but cocooned in its own world. "We have never been invited to join any prime minister's party on his foreign visits, Delhi and Kolkata papers reach us very late, after a day or two, that too the dak edition,' said Geoffrey Yaden, editor of the Nagaland Post, the main daily newspaper in the state. "They don't understand us properly, they write to please their egos. Nobody has the time and interest to understand our people or to make serious efforts to create bridges and strengthen national feelings here. Are politicians sitting in Delhi are bothered about us or the nation?" he lamented.

I know it is very difficult to have a Delhi leader or social activist or cultural tsar to find time for a northeast visit. How many of us would go to Manipur or Nagaland or Arunachal for a family trip? Do we know that the most scintillating lakes, mountains, rivers and forests are in the northeast, bettering even Kashmir's panorama? Unfortunately the northeast has yet to register in our minds as markedly as Hardwar, Manali, Goa or Rameshwaram.

Corruption to the northeast's politicians is 'taught' by politicians in New Delhi. Even to get a central grant released for these states, central ministers and their durbaris have to be suitably 'pleased'. The grants that go to the northeast finally come back in large parts to the Delhi durbar through traders, contractors, commission agents and sanctioning ministers. The rest is divided amongst local 'beneficiaries', including the insurgents.

In view of the infiltration threat faced by Nagaland and other northeastern states, an observation by E Ramamohan, the former director general, Border Security Force, who was with me in Kohima, should be an eyeopener. He warns about the insurgent groups' long-term planning for 2015 -- "Today there are several Islamic fundamentalist insurgent groups in Assam, created with the help of the Director General Forces Intelligence of Bangladesh and Pakistan's Inter Services Intelligence. The main groups are the Muslim United Liberation Front of Assam, the Muslim United Tigers of Assam and the Islamic Liberation Army of Assam... what is more interesting that these Islamic fundamentalist groups have not started operations so far. Interrogation of the suspects and intelligence reports have revealed that they are in a preparation phase. Motivating and recruiting cadres, training them in Pakistan, stockpiling arms and explosives for the insurgency is their present strategy. The target is (to launch an assault) in 2015."

Why can't we understand that India shrinks from every inch that is occupied by Bangladeshi infiltrators in our territory? In less than 100 years India has shrunk like no other nation on earth.

We lost Taxila, Karachi, Dhaka. Post independence, we lost 1.25 lakh square kilometres of land to Pakistan and China. Beijing still eyes Arunachal Pradesh.

Then Indians lost lands and homes in the Kashmir valley and became refugees for the 'sin' of supporting India. Now, jihadis, Maoists and church-supported insurgents want their share. Where will this all lead to? All the power, position, money and glitter weigh nothing before the question of the nation's sovereignty and territorial integrity. At least in the northeast, people feel nobody listens to their woes in Delhi.

■

Karnataka

ABVP Opposes Jagannatha Rao Committee Report

ABVP has demanded the withdrawal of the government circular which states that scholarships may be given only to SC/ST students who have secured 60 per cent marks in accordance with the recommendation of the Jagannatha Rao Report.Earlier scholarships were being accorded to SC/ST students without any restrictions, but with the implementation of this report, injustice has been done to the SC/ST student.If this order not withdrawn, ABVP will take a protest march to all the deputy commissioner's offices in the State demanding the withdrawal of the order.

The implementation of this order will be an obstacle for SC/ST student in pursuing higher education. The ABVP has also opposed the order which says that only tuition fees and laboratory fees is exempted for women students up to degree level.

Tamilnadu

ABVP Plea to Amend OBC Creamy Layer List

ABVP has appealed to the Central Government to amend the creamy layer list concerning Other Backward Classes (OBCs) for whom 27 per cent has been reserved. A resolution to this effect was passed at the State Committe meeting of the ABVP held recently.A release from ABVP said the creamy layer list should be amended to exempt children of private medical practitioners, advocates, engineers and film artistes and heirs of sports personalities.

The Centre should also consider fixing the income limit in this regard and an expert committee should be constituted. The Government of Tamil Nadu was planning to introduce a rule that only those who took the same major in undergraduate as well as and postgraduate courses could become lecturers. Such a rule should not be brought into effect immediately as it might affect those who had completed their graduation and were doing postgraduation in a different major.

The rule could be introduced after a gap of 10 years, he suggested.The ABVP also urged the government to monitor the functioning of educational institutions to prevent them from collecting donations, exorbitant fees and violating rules in admissions.The government should ensure that institutions without recognition were dealt with severely.

Punjab

Blood Donation Camp by Punjab University, Chandigarh Unit

ABVP,Punjab University,Chandigarh,organised blood donation camp on 26th march,2008.52 students donated their blood to pay their tribute to the Trimurti Bagat Singh,Sukhdev and Raj Guru ,who have laid down their lives for freedom of our country.Sh.Ramesh Pappa,Secretary general WOSY was the chief speaker while Shri .Hira Lal Mahajan,a social worker presided over the function. Prof.Naval Kishor,Dean,student welfare, Ku.Mukta Sharma,ABVP national executive member were also present on this occassion.

Himachal Pradesh

Dharna in support of ongoing agitation of Tibteians

ABVP Shimla unit today organised a dharna in support of ongoing agitation of Tibteians. Students from HP university and various colleges participated in the dharna.A good no.of tibetians also joined it. Shri.Ramesh Pappa,WOSY Sec.Gen was the chief speaker on this occassion.

Shri.Nitin Vyas, Ku.Manchali Thakur, ABVP State Sec., Shri.Naveen Sharma, Unit President HP university, Shri.Bihari Lal,North Zone Org.Sec,Shri.Umesh Sharma,ABVP State Org.Sec,Ku.Rajni Thukral, member national executive were also present on this occassion.

Jammu & Kashmir

ABVP Organizes Blood Donation Camp at Jammu University

The Jammu University unit of ABVP today organized a blood donation camp in the university campus.The camp was dedicated to the martyrs of India's first war of independence, launched in the year 1857. More than 50 volunteers donated blood in the camp.

Earlier, in the beginning, floral tributes were paid to the martyrs of 1857. Dinesh Gupta, chairman, Citizens Cooperative Bank Ltd was the chief guest, while Sunil Ambekar, all India organizing secretary of ABVP, was the main speaker.While speaking, Ambekar dwelt upon the role of youth in nation building. He said that today youth has no need to sacrifice lives on the pattern of 1857 martyrs, but what they need was to get involved in various humanity service programmes like blood donation camp.

At the conclusion, Shvetan Sharma, secretary ABVP JU, presented the vote of thanks.

Delhi

Candle march by ABVP in support of Tibetans

Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad took out a candle march in Jawaharlal Nehru University in New Delhi against the atrocities perpetuated on Tibetans by Chinese army. Hundreds of students, demanded liberation of Tibet on April 17. Addressing the demonstrators Dr Kuldip Agnihotri of Bharat Tibet Sahayog Manch alleged that the Government of India has surrendered before the Chinese Government. Participation of Chinese security personal in Olympic torch relay at Rajpath is a serious matter for the country. The Government of India should apologise before the nation. He said the Indian Parliament had resolved on November 14, 1962 to liberate every inch of Indian land from China, but the government appears to have forgotten the resolution. He appealed to the Government to make efforts to liberate Indian land from illegal occupation of China. Dr Agnihotri further said the Olympic Torch relay taken out on Rajpath did not have participation of the people of India.Shri Manoj Kumar, State Vice President and Shri Devendra Sahu, President of JNU unit were also present on the occasion.

ABVP welcomes SC judgment on OBC reservation

ABVP welcomed the Supreme Court judgment on 27 per cent reservation to OBCs in central educational institutions. "The ABVP clearly believes that reservation to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Castes was a historical necessity and recognising the social reality it should be implemented within the ambit of the constitutional framework. The ABVP believes that the benefit of the reservation should reach to the needy people and formula of creamy layer should also be implemented. Apart from it, there is a need to review the reservation to ascertain the number of people who received the benefit. Those who have become forward availing the benefit of reservation should be moved out of the ambit of the reservation. The ABVP also believes that only the politicians and the government should not take the decision on the issues like reservations, but the opinion of the people of different sections of the society like educationists, former judges, social activists, members of students organisations, etc. should also be sought.

हिमाचल प्रदेश के पूर्व कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महामंत्री सुरेश भट्ट

ABVP Activists Protesting Against Marxist Violence in Kerala at Madurai, Tamilnadu

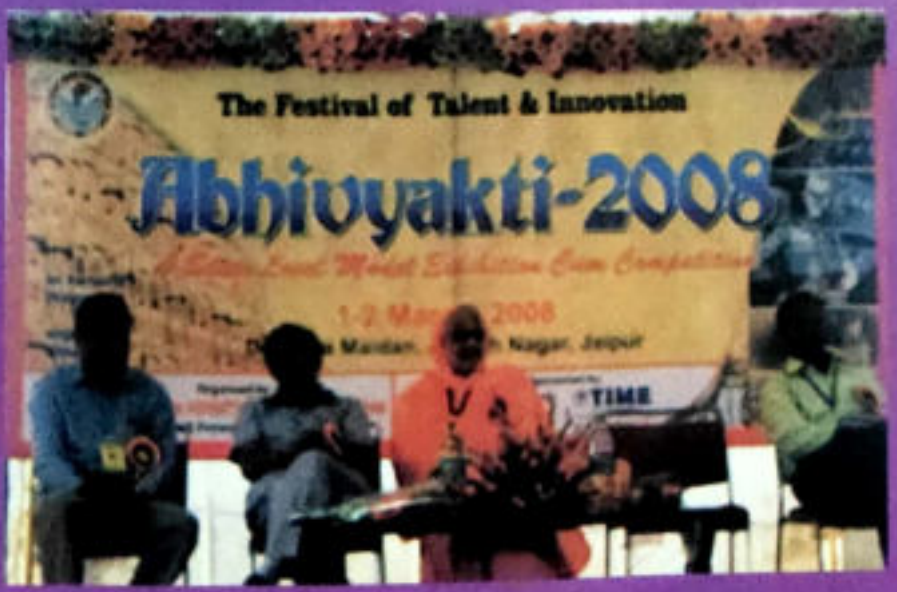

Inaugural Function of Abhivyakti 2008 - State Level Model Exhibition Cum Competition at Jaipur, Rajasthan

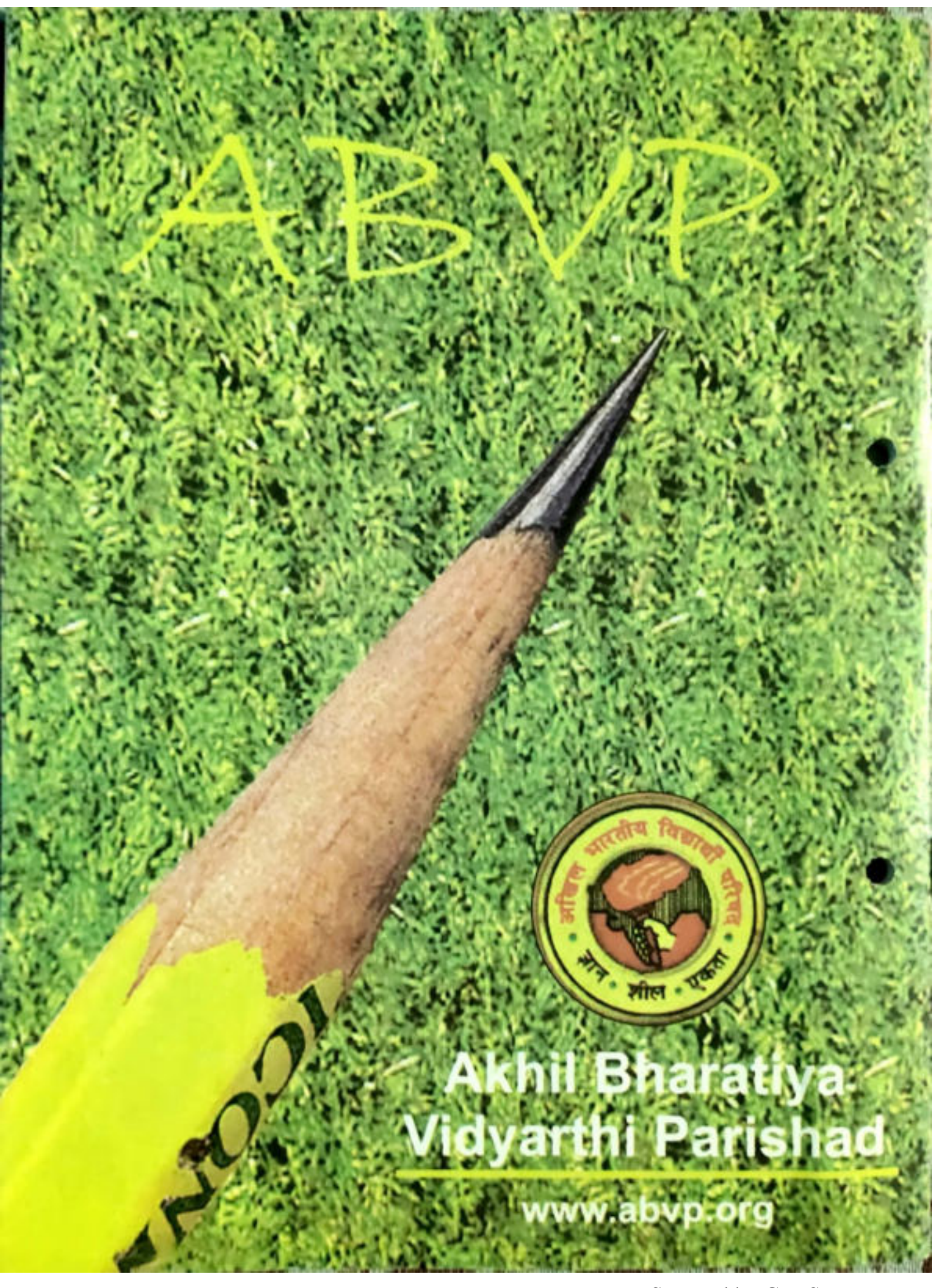
ABVP
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद
ज्ञान • शील • एकता
Akhil Bharatiya
Vidyarthi Parishad
www.abvp.org